रोहतक, सोमवार 2 फरवरी 2026 ■ फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष-01 ■ वर्ष : 29, अंक : 364 ■ पृष्ठ : 14 मूल्य : 3.00 मौसम अधि. 23.5, न्यून. 6.0 haribhoomi.com

हरिभूमि

हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

हमने तीन कर्त्तव्य तय किए : वित मंत्री

- इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना।
- लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना।
- सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध करवाना।

आम बजट 2026-27

रिकॉर्ड 9वीं बार पेश किया बजट

फिसलन भरी पिच पर
सिक्सर की तैयारी

सीतारमण द्वारा पेश बजट भविष्य का रोड मैप तैयार करता है। बजट में भले ही लोगों को तुरंत राहत न मिले लेकिन आगे चलकर रोजगार, निवेश और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। वैश्विक अस्थिरता के बीच यह बजट 2047 के विकसित भारत का रास्ता तय करेगा।

53.5
लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया वित्त मंत्री सीतारमण ने

प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन

क्षेत्र	आवंटित राशि
रक्षा	7.8 लाख करोड़
बुनियादी ढांचा	12.2 लाख करोड़
रेलवे	2.8 लाख करोड़
बायोफार्मा	10,000 करोड़
इलेक्ट्रॉनिक्स	40,000 करोड़
एमएसएमई	10,000 करोड़
शिक्षा	1.35 लाख करोड़

12.2
लाख करोड़ रुपये सरकारी पूंजी व्यय

1.4
लाख करोड़ राज्यों को कर के लिए आवंटित

28.7
लाख करोड़ रुपये शुद्ध कर संग्रह

17.2
लाख करोड़ रुपये सकल बाजार उधारी

राजकोषीय घाटा
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3 प्रतिशत लक्ष्य रखा

विकास दर लक्ष्य
अर्थव्यवस्था के लिए 7 फीसदी की सतत उच्च विकास दर हासिल करना

सेंट्रल डेस्क ▶▶ रोहतक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया। यह बजट तीन कर्तव्यों के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है। उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन के तहत समावेशी विकास सुनिश्चित करना। बजट में जेन जी और ऑरेंज इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें शिक्षा, केयरगिवर प्रशिक्षण और डिजिटल कंटेंट निर्माण के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान देते हुए रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर छूट को 10 वर्ष तक बढ़ाने की ऐतिहासिक घोषणा शामिल है। सामान्य नागरिक और उद्योग दोनों के लिए बजट का फोकस ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रहा। प्रमुख घोषणाओं में विदेशी प्रेषण कर (ओवरसीज रेमिटेंस टैक्स) का सरलीकरण, विदेशी परिसंपत्तियों के लिए एकमुश्त खुलासा योजना और सात नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा शामिल है। मौजूदा वैश्विक माहौल और टैरिफ के टैरर की फिसलन भरी पिच पर वित्तमंत्री ने लगातार नौंवा बजट पेश करते हुए छक्का लगाने की तैयारी की है।

नौवें बजट पर निर्मला के 9 मंत्र

1. आयकर : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

आयकर स्लैब	कर दर
4,00,000 तक की आय	कोई कर नहीं
4,00,001 से 8,00,000	5%
8,00,001 से 12,00,000	10%
12,00,001 से 16,00,000	15%
16,00,001 से 20,00,000	20%
20,00,001 से 24,00,000	25%
24,00,001 से अधिक	30%

2. स्वास्थ्य : कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है।

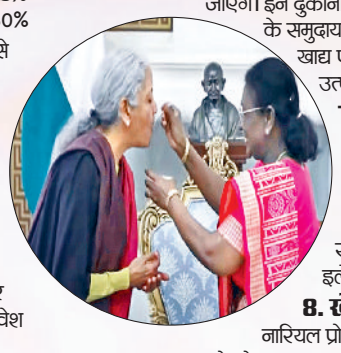

3. डिफेंस : डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी।

4. इंफ्रास्ट्रक्टर : 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे।

5. शिक्षा : 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

6. महिलाएं : लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी-मार्ट बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे।

7. ग्रीन एनर्जी : सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।

8. खेती और पशु-मछली पालन : नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।

9. खेल : बजट में खेल मंत्रालय के लिए 4479.88 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें 1000 करोड़ की वृद्धि की गई है। यह पैसा खेलों के विस्तार में लगाया जाएगा।

बजट पर पढ़ें विशेष पेज : 2, 3, 4, 5

सस्ता

- कैंसर की दवाएं
- सात दुर्लभ बीमारियों से संबंधित विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दवाएं, औषधियां और खाद्य पदार्थ
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाएं
- माइक्रोवेव ओवन के प्रमुख कलपुर्जे
- विमान के इंजन सहित कलपुर्जे
- 'सोलर ग्लास' के कलपुर्जे
- परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान
- महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान

महंगा

- कम लागत वाले आयातित छाते
- पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
- एटीएम/कैश डिस्पेंसर मशीन और उसके कलपुर्जे
- विदेशी लोगों के लिए फिल्म और प्रसारण उपकरण
- चिड़ियाघर में बाहर से जानवर व पक्षी लाना
- अमोनियम फॉस्फेट/नाइट्रो-फॉस्फेट उर्वरक और नेफ्था जैसे उर्वरक
- कॉफी भूनने, बनाने या बेचने की मशीन
- अरंडी खल

'वीबी-जी राम जी' के लिए 95,000 करोड़ आवंटित

केंद्र सरकार ने नई योजना 'वीबी-जी राम जी' को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है।

पर्यटन : 10 हजार गाइड्स को मिलेगी ट्रेनिंग

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,हजार गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों। इससे पर्यटन उद्योग को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।

हैंडलूम: नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन

नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम तैयार किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर जोर होगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2026 में लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से एंटरप्राइज मालिक बनने में मदद करने की योजना बना रही है। साथ ही क्लस्टर-लेवल फेडरेशन के भीतर कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे।

विदेश में पढ़ाई और इलाज सस्ता

2026-27 में विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स) को कम करने का ऐलान किया है। अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा भेजे तो टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

खनिज: रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा

केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।

बाजार को नहीं भाया बजट
निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

नई दिल्ली (भाषा)। बजट 2026-27 के दिन रविवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से निवेशकों के करीब 9.40 लाख करोड़ रुपये डूब गए। वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाने की बजट घोषणा शेयर बाजार को रास नहीं आई और यह कुछ ही देर में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत तक लुढ़क गया। हालांकि, बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ कारोबार के अंत में 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत के नुकसान के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा, ये 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। इस बड़ी गिरावट के चलते बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 9,40,581.75 करोड़ रुपये घटकर 4,50,61,658.60 करोड़ रुपये (4.90 लाख करोड़ डॉलर) रह गया।

नारियल उत्पादन के लिए संवर्धन योजना

सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसमें नारियल उगाने वाले मुख्य राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

पूर्वोत्तर के पांच राज्यों अरुणाचल असम सिक्किम मिजोरम त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनेंगे

विकसित भारत का साफ रोडमैप है बजट : पीएम मोदी

केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दिखाता है। यह सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक साफ रोडमैप तैयार करता है। यह एक ऐसा अनोखा बजट है जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने, महंगाई को कंट्रोल में लाने पर फोकस करता है और इसके साथ ही, इस बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का कॉम्बिनेशन भी है। - ***नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

हरियाणा के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान देगा केंद्रीय बजट

बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज है। वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड रुपये का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनामिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा। बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10000 करोड रुपये का प्रावधान हरियाणा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। - **नायब सैनी, मुख्यमंत्री**

दूरदर्शी व संतुलित बजट, कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे

केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला एक दूरदर्शी और संतुलित बजट है। यह शिक्षा, खेल और कृषि तीनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और नवाचार को नई गति देता है। शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, एनआईडी जैसे संस्थान, हर जिले में छात्रावास सुविधा और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आधुनिक टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को अनुसंधान और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करेंगे। -**कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व वित्त मंत्री**

सरकार के पास कोई नीति समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं

सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई तथा किसानों की भी उपेक्षा हुई है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। -**मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष**

केंद्रीय बजट में हरियाणा के सात जिलों को सीधा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बजट-2026 में हरियाणा के 7 जिलों को सीधी तौर पर फायदा होता दिख रहा है। अंबाला, हिसार, करनाल की हवाई पट्टियां सी-प्लेन के लिए डेवलप होंगी। इसके अलावा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनाने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए केंद्र बनेंगे। पंचकूला फार्मा हब के लिए डेवलप होगा। पंचकूला में एसोसिएटेड बायोफार्मा और बायोफार लाइफसाइंसेज जैसी कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और जड़ी-बूटी से दवाइयां बनाती हैं, और ये सभी दवाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए नियमों के अनुसार बनाई जाती हैं। सोनीपत के खरखौदा और गुरुग्राम के मानेसर में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली-गुड़गांव-फरीदाबाद जैसे कॉरिडोर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क को फंडिंग की घोषणा की गई है। इससे हरियाणा को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

- अंबाला, हिसार करनाल की हवाई पट्टियां सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी
- गुरुग्राम-फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनेंगे, पंचकूला फार्मा हब के रूप में डेवलप होगा

पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के प्रयासों से शुरू हुआ था म्यूजियम का निर्माण कार्य

राखीगढ़ी बनेगा टूरिज्म हब, 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की लिस्ट में होगा शामिल, गाइड की नियुक्ति होगी

हिसार (हरिभूमि न्यूज)। राखीगढ़ी अब देश के 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। इस पहल से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी के इस केंद्र को अब इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के प्रयासों से राखी गढ़ी में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2017 में म्यूजियम बनाने की शुरुआत की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राखीगढ़ी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां पाथ-वे बनाया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां कल्चरल कार्यक्रम किए जाएंगे।

राखीगढ़ी को बजट में क्या मिला

- केंद्र सरकार राखीगढ़ी में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पाथ-वे का निर्माण करेगी।
- राखी गढ़ी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
- साइट पर लोकल गाइड, विजिटर सुविधा, रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटी शुरू होंगी।
- ऐतिहासिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाएंगे।

पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों का होगा विकास : सीतारमण ने बजट भाषण में लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस समेत पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों का विकास 'जीवंत अनुभव वाले सांस्कृतिक गंतव्यों' के रूप में करने का भी प्रस्ताव रखा।

कैप्टन अभिमन्यु ने वर्ष 2017 में म्यूजियम बनवाने की शुरुआत की

राखीगढ़ी को 15 आईकॉनिक पुरातात्विक स्थलों में शामिल करने की घोषणा से क्षेत्र को बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। राखीगढ़ी में जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, वह प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के प्रयासों की ही देन है। जब वे प्रदेश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने वर्ष 2017 म्यूजियम बनाने की शुरुआत की थी। करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से इस म्यूजियम का निर्माण कार्य पूरा होना है। राखीगढ़ी में सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज के लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये जारी किए गए है जो कि टीलों पर होने वाले उत्खनन के कार्य सहित, सड़कें, आधुनिक सीवरेज, बिजली की लाइट और पर्यटन से जुड़ी अन्य सुविधाओं के लिए खर्च किए जाएंगे।

"यह बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का घोषणापत्र है। यह विकसित भारत के सपने को साकार करने का महाकाव्य है। यह बजट देश के उन मूल वर्गों पर केंद्रित है, जिनके विकास से देश की प्रगति सुनिश्चित होती है गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही योजनाओं से गरीबी तेजी से कम हो रही है और यह बजट गरीब को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

-शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री

कृषि क्षेत्र : आय में विविधता आएगी और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार के अवसर पैदा होंगे

पशु-मत्स्य पालन बनेगा ग्रामीण आय की रीढ़

1.63
लाख करोड़ रुपये का कृषि एवं ग्रामीण बजट

पशुपालन-मत्स्य पालन
क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा देंगे आय के मौके बढ़ाने पर फोकस

नारियल से चंदन तक
नारियल प्रोत्साहन योजना से 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा

ग्रामीण रोजगार सृजन
आय बढ़ाने के लिए कृषि से जुड़े सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के इरादे से केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को बहुआयामी स्वरूप देने की पहल की गई है। पशुपालन, मत्स्य पालन, नारियल, काजू, कोको और पहाड़ी बागवानी जैसे क्षेत्रों को केंद्र में रखकर सरकार ने किसानों की आय में विविधता लाने और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करने की रणनीति अपनाई है। बजट में की गई घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है।

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि से जुड़े सहायक क्षेत्रों पर बड़ा फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशुपालन, मत्स्य पालन, नारियल और उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार अवसर पैदा करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट का साफ संदेश है कि अब खेती सिर्फ फसल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों की आमदनी के नए स्रोत तैयार किए जाएंगे। सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, मत्स्य पालन और पशुपालन को प्रमुखता दी गई है।

1 आय विविधीकरण पर जोर
बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को प्रमुख स्थान मिला है।

2 रोजगार-सेवाओं का विस्तार
पशुपालन क्षेत्र को संगठित और आधुनिक बनाने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं। खासतौर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

प्रमुख घोषणाएं
- 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव।
- ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना की शुरूआत।
- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और निजी कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन
- आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं का विस्तार
- इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पशुपालन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई ऋण-सम्बद्ध सब्सिडी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन आधारित इकाइयों को बढ़ावा।

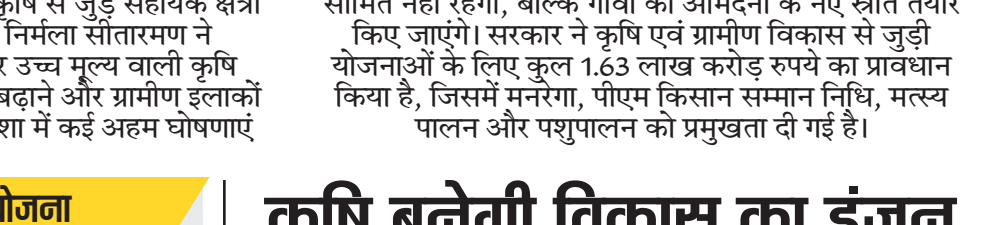

तटीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत
- मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर बजट में बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं।
- सरकार 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का समेकित विकास करेगी।
- मछली पालन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- महिलाओं की अगुवाई वाले समूहों और एफपीओ को बाजार से जोड़ना।
- इससे मछुआरों की आय बढ़ाने के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एकीकृत मूल्य श्रृंखला का निर्माण
- उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक आधुनिकीकरण
- सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और पशुपालन-एक संगठित उद्योग के रूप में उभरेगा।

नारियल संवर्धन योजना
वित्त मंत्री ने तटीय किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की, जिसके तहत पुराने और गैर-उत्पादक नारियल वृक्षों को हटाया जाएगा उनकी जगह नई और अधिक उत्पादक किस्में लगाई जाएंगी। सीतारमण ने बताया कि करीब एक करोड़ किसान और लगभग तीन करोड़ लोग नारियल पर निर्भर हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। यह योजना तटीय राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने और नारियल आधारित उद्योगों को मजबूती देगी।

कृषि बनेगी विकास का इंजन
बजट 2026-27 में कृषि को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए पशुपालन, मत्स्य पालन, नारियल, बागवानी और उच्च मूल्य कृषि को विकास का इंजन बनाने की कोशिश की गई है। इन घोषणाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण भारत में टिकाऊ रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यदि ये योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

काजू व कोको मिलेगी पहचान
भारतीय काजू और कोको कार्यक्रम की शुरुआत

उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की रणनीति पर होगा काम

2030 तक इन्हें विश्वस्तरीय प्रीमियम ब्रांड बनाने का लक्ष्य

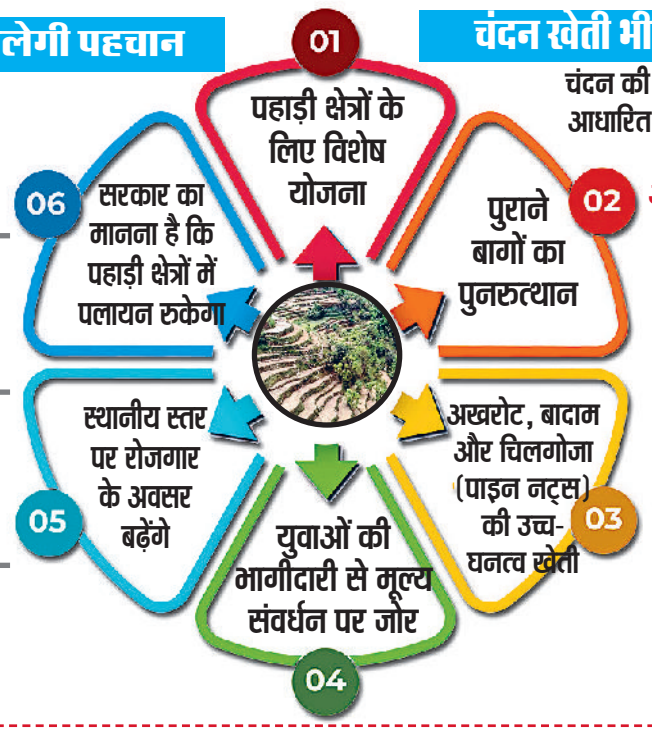

चंदन खेती भी देगी मुनाफा
चंदन की खेती को बढ़ावा, चंदन आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण
भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर से जुड़े चंदन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन

भारत विस्तार की शुरुआत
बजट में भारत विस्तार की भी घोषणा की है। भारत विस्तार के जरिए किसानों को कई तरह के एक्सिस मिलेंगे। इसके जरिए किसानों के पास किसान कॉल सेंटर सर्विस का सीधा एक्सिस होगा। इसके साथ ही किसान एपीआई के जरिए मौसम की जानकारी ले पाएंगे।

निवेश से किसानों की आय दोगुनी होगी

प्रोफेसर रामकुमार खटकड़
पूर्व अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, हकृवि हिसार।

हिसार। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1 लाख 62 हजार 671 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमान 1 लाख 51 हजार 853 करोड़ की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। संसाधनों की कमी और उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए बजट आवंटन का एक विश्लेषण और प्रस्तावित बजट 2026-27 : कृषि क्षेत्र का आवंटन (अनुमानित और प्रस्तावित) आवश्यक/प्रस्तावित आवंटन (सुझाव) कारण 15 से 20 हजार करोड़ गिरते भूजल स्तर और जल सुरक्षा के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को व्यापक स्तर पर लागू करना अनिवार्य है। 10 से 12 हजार करोड़ कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दो हजार-तीन हजार करोड़ ड्रोन और सेंसर आधारित खेती के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। जलवायु लचीली खेती अनुसंधान और विकास पर केंद्रित 5 हजार करोड़ (समर्पित फंड) अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान के कारण जलवायु-अनुकूल बीजों और तकनीकों पर निवेश भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। केंद्रीय बजट 2026-27-कृषि क्षेत्र में तकनीक और जल संचयन के लिए 'क्रांतिकारी रोडमैप' की आवश्यकता। संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन स्वागत योग्य है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, देश में गहराते जल संकट, जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं और कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए, क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कुछ विशिष्ट मदों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। वर्तमान में जल की कमी एक गंभीर चुनौती है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए आवंटन को मौजूदा स्तर से दोगुना करने की आवश्यकता है ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे और जल का अपव्यय कम हो।

फोकस पर जेन जी : एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स सिर्फ शौक नहीं, हैं करियर ऑप्शन

सेंट्रल डेस्क (रोहतक)। दशकों तक केंद्रीय बजट एक संख्याओं से भरी औपचारिक प्रक्रिया रहा है, जिसमें राजकोषीय घाटा लक्ष्य, कर स्लैब, सब्सिडी और उधारी जैसे मुद्दे प्रमुख होते थे और जिनका विश्लेषण मुख्यतः अर्थशास्त्री और बाजार करते थे। लेकिन बजट 2026-27 इस परंपरा से एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। बिना किसी चकाचौंध भरी घोषणाओं के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के भावनात्मक और सांस्कृतिक दायरे का विस्तार किया है। इनमें उन मुद्दों को शामिल किया गया है जो मिलेनियल्स और जेन-जी पीढ़ी के साथ गहराई से जुड़ते हैं। रचनात्मक करियर, सतत पर्यटन, एआई, वैश्विक जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को शामिल कर यह बजट दिखाता है कि आर्थिक नीति अब इस बात से भी जुड़ रही है कि युवा भारतीय कैसे जीते, काम करते और सोचते हैं। इस तरह बजट ने 'उबाऊपन' को कुछ हद तक कम कर दिया है। बजट 2026-27 की खास बात केवल खर्च के मद नहीं हैं, बल्कि यह भी है कि वह किन वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। यह बजट उस पीढ़ी के जीवन अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है जो संपत्तियों से अधिक अनुभवों को, स्थायित्व से अधिक उद्देश्य को और भौतिक सफलता के साथ मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देती है। यह संयोग नहीं है। भारत की जनसंख्या बड़ी हद तक युवा, शहरी और डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है, और आर्थिक नीति अब सांस्कृतिक व सामाजिक बदलावों से अलग नहीं रह सकती।

ऑरेंज इकोनॉमी का प्रवेश
पहली बार केंद्रीय बजट ने औपचारिक रूप से ऑरेंज इकोनॉमी या रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मान्यता दी है। रचनात्मकता, संस्कृति, डिजाइन और बौद्धिक संपदा पर आधारित एनीमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, डिजाइन, संगीत, फिल्म और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों इसमें शामिल किया गया है। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें अब युवा भारतीय जोखिम भरे शौक की बजाय वैध और आकर्षक करियर के रूप में देखते हैं। सीतारमण का एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्र पर ध्यान, जिसमें 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता का अनुमान है।

नए दौर का पर्यटन
बजट यह भी स्वीकार करता है कि युवा भारतीय और वैश्विक यात्री अब पर्यटन को अलग तरीके से अनुभव करते हैं। स्मारक-केंद्रित चेकलिस्ट पर्यटन की जगह अब अनुभवात्मक, पारिस्थितिक और उद्देश्यपूर्ण पर्यटन पर जोर दिया गया है। हिमालय और घाटों में पर्वतीय ट्रेल्स, तटीय क्षेत्रों में कछुआ संरक्षण ट्रेल्स और पर्यावरण-संवेदनशील स्थलों का विकास उस पीढ़ी की पसंद को दर्शाता है जो सततता, रोमांच और प्रामाणिकता को महत्व देती है। पहला ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करने की पहल संरक्षण को वैश्विक सॉफ्ट पावर और ईको-टूरिज्म से जोड़ती है।

वैश्विक उपभोग सस्ता
व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 10% करना एक ऐसी वास्तविकता को स्वीकार करना है जिसे नीति निर्माता पहले कम महत्व देते थे। यह है भारतीय उपभोक्ता वैश्विक हैं। जेन-ज़ी और मिलेनियल्स अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और एक्सेसरीज खरीदते हैं, बेहतर कीमतों और ब्रांड आकर्षण के कारण। उच्च श्रेणी के स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेयरेबल्स और ब्रांडेड परिधान इस मांग में प्रमुख हैं। यह टैरिफ कटौती विदेश से लौटने वाले भारतीयों और पर्यटकों को भी लाभ देती है।

एआई: नारे से आधारभूत ढांचे तक
बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केवल एक भविष्यवादी शब्द नहीं, बल्कि शासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार में एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में उभरा है। सीतारमण द्वारा एआई का बार-बार उल्लेख यह दर्शाता है कि यह तकनीक अर्थव्यवस्था का केंद्रीय हिस्सा बन रही है। भारत-विस्तार जैसे बहुभाषी एआई टूल्स, एआई आधारित जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म, स्कूल पाठ्यक्रम में एआई का समावेश और कृषि परामर्श प्रणालियों में इसका उपयोग संकेत देते हैं कि एआई को नवाचार नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट ध्यान
एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा ध्यान है। उत्तर भारत में नए निमहंस-2 की स्थापना और रांची व तेजपुर में संस्थानों के उन्नयन की घोषणा यह दर्शाती है कि तनाव, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य अब खुलकर स्वीकार किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को स्वीकार करने में कम हिचकती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर बजट यह दर्शाता है कि कल्याण भी एक आर्थिक मुद्दा है। उत्पादकता, सीखने की क्षमता और सामाजिक एकजुटता सभी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2.5 लाख करोड़ आवंटित किए

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025-26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 9.44 प्रतिशत अधिक है। बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 1.73 लाख करोड़ पुलिस मद के लिए निर्धारित किया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को 2026-27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

केंद्रीय बजट में जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान

चंडीगढ़ को 5,720.17 करोड़
बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है, जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों की जानकारी एकत्रित करके और उनकी पड़ताल करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।

पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं

केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को पहले की तरह 6,000 सालाना ही बनाए रखा है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल तीन बराबर किस्तों में 2,000-2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे। बजट से पहले दिसंबर महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने पीएम किसान की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने के कारण 6,000 की सालाना मदद अब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा किसानों ने टैक्स में राहत, खेती के लिए सस्ता कर्ज और लंबी अवधि के लिए आसान फाइनेंसिंग की भी मांग रखी थी। हालांकि बजट 2026 में इन मांगों पर फिलहाल कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया है, जिससे कई किसानों को थोड़ी निराशा भी हुई है। बता दें कि, बजट 2024-25 में कृषि मंत्रालय के लिए 1,32,469 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। उस समय का मुख्य ध्यान कृषि अनुसंधान के व्यापक बदलाव और 109 नई बीजों की किस्मों के परीक्षण पर था।

आम बजट 2026-27

"आम बजट लोगों की भावनाओं और उम्मीदों पर खरा उतरता है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद यह बजट देश के रक्षा तंत्र को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को और पुख्ता करता है। बजट का मुख्य फोकस तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर है। -राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री"

15 फीसदी बढ़ाया गया इस बार रक्षा बजट। सेनाएं होंगी और आधुनिक।

वैश्विक चुनौतियों के बीच एक लाख करोड़ से अधिक बढ़ा बजट

रक्षा बजट पर ऑपरेशन सिंदूर की छाप

3,65,478.98 करोड़ रुपये रक्षा सेवाएं (राजस्व) के लिए आवंटित

2,19,306.47 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए दिए

17.24 % रक्षा सेवाएं (राजस्व) व 21.84% पूंजीगत व्यय वृद्धि दर्शाते है

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय बजट में ऑपरेशन सिंदूर की छाया स्पष्ट रूप से देखने को मिली। सरकार ने अपनी सेनाओं को मजबूती देने के लिए रक्षा बजट को करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभरकर सामने आई है। बजट दस्तावेजों और घोषणाओं पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने अपनी सेनाओं को मजबूत करने का स्पष्ट और ठोस संदेश दिया है। बदलते वैश्विक हालात, क्षेत्रीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों से कोई समझौता नहीं करेगा। यह संकेत रक्षा बजट में की गई भारी बढ़ोतरी से मिलता है।सरकार ने 2026-27 के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6,81,210 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 15 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी न केवल आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे की रणनीतिक सोच भी उतनी ही अहम मानी जा रही है। रक्षा बजट में सबसे ज्यादा जोर आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद पर दिया गया है। कुल पूंजीगत व्यय 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई जरूरतों और अनुभवों ने रक्षा नीति निर्धारण को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

- सरकार सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाएगी
- थल, वायु और नौसेना को संतुलित रूप से मजबूती मिलेगी, ऑपरेशन में दिक्कत नहीं होगी
- रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग मजबूत होंगे, देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा

मजबूत होगी सेना

सेंट्रल डेस्क(रोहतक)। केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षके 6.81 लाख करोड़ रकी तुलना में 1.04 लाख करोड़ की वृद्धि है।

रक्षा व्यय

2026-27	7,84,678 करोड़ रुपये
2025-26	6,81,210 करोड़ रुपये

ब्रेकअप

राजस्व व्यय	5,53,668 करोड़ रुपये
पेंशन	1,71,338 करोड़ रुपये
आधुनिकीकरण	2.19 लाख करोड़ रुपये
विमान व एयरो इंजन	63,733 करोड़ रुपये
नौसैनिक बेड़ा	25,023 करोड़ रुपये

राफेल सहित कई प्रोजेक्ट लाइन में

रक्षा मंत्रालय के पास कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिनमें राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के अनुबंध भी शामिल हैं। 2025-26 में पूंजीगत व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित

हवाई पुर्जों पर कस्टम में छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक पुर्जों और घटकों पर मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) से छूट देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहाल के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर भी मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी।

सुधरेगी सेहत, 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाए जाएंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय को 10% ज्यादा बजट आवंटित

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इसके साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर चिकित्सा पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है। ये चिकित्सा हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसरों के रूप में विकसित किए जाएंगे, जहां इलाज, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

1 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

- **02** नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
- **03** नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे
- **17** लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- **1,000** क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा

स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख घोषणाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ का आवंटन

10 प्रतिशत की कुल बजट वृद्धि, निजी भागीदारी से 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब

एचपी के लिए 1,000 करोड़, 1 लाख नए पेशेवर

मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ पर अतिरिक्त फोकस

एनएचएम और आयुष्मान भारत का बजट बढ़ा

सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों पर फोकस

- बजट 2026-27 में पहली बार सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एचपी) के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मौजूदा एचपी संस्थानों को उन्नत किया जाएगा
- सरकारी और निजी क्षेत्र में नए एचपी संस्थान खोले जाएंगे
- अगले 5 वर्षों में एक लाख नए एचपी तैयार किए जाएंगे

इनमें ये प्रमुख क्षेत्र

- ऑप्टोमेट्री
- रेडियोलॉजी
- एनेस्थीसिया
- ओटी टेक्नोलॉजी
- एप्लाइड साइकोलॉजी
- व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे।
- युवाओं को कौशल आधारित रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे।

बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए मजबूत प्रणाली

- बुजुर्गों के लिए सहायक और देखभाल सेवाओं की मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी
- 07 नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना होगी
- 07 पहले से मौजूद संस्थान होंगे अपडेट
- 17 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म
- कैंसर व शुगर की दवाइयां होंगी सस्ती
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नए संस्थान बनेंगे
- नए अस्पतालों की स्थापना होगी

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में बजट बढ़ा

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
- पहले : 2025-26: 37,100.07 करोड़ रुपये
- अब 2026-27: 39,390 करोड़ रुपये
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- आवंटन बढ़ाकर 8,995 करोड़ से 9,500 करोड़ रुपये
- 5.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

रोजगार के मौके बढ़ेंगे

बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को केवल उपचार तक सीमित नहीं रखकर रोजगार, अनुसंधान और वैश्विक अवसरों से जोड़ना चाहती है। बढ़ा हुआ बजट, क्षेत्रीय चिकित्सा हब और सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों पर फोकस आने वाले वर्षों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

एम्स-आईसीएमआर व रिसर्च संस्थान मजबूत

- एम्स दिल्ली का बजट बढ़ाकर 21,901.98 करोड़ से 22,343.97 करोड़ किया
- आईसीएमआर का बजट बढ़ाकर 5,238.70 करोड़ से 5,500.92 करोड़ किया
- करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि
- सरकार का कहना है कि इससे चिकित्सा अनुसंधान, नई दवाओं और तकनीकों के विकास को गति मिलेगी।

मानसिक स्वास्थ्य पर जोर

- राष्ट्रीय टूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- बजट 45 करोड़ से बढ़ाकर 51 करोड़
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- 2026-27 के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान
- इन योजनाओं के जरिए टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ऑनलाइन परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

शिक्षा — कुल 1.45 लाख करोड़ रुपये का आवंटन — यह पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत अधिक

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र खोले जाएंगे

- 01 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोले जाएंगे
- 05 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापना
- 04 टेलीस्कोप/खगोल विज्ञान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
- 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- 15000 माध्य. स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना

प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनेंगी

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। बजट में मुंबई स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में 'कंटेंट लैब' स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव है। बजट 2026-27 में शिक्षा को रिकॉर्ड आवंटन, कुल बजट का बड़ा हिस्सा छात्रों और संस्थानों पर खर्च होगा। बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार ने अब तक का सबसे मजबूत वित्तीय खाका पेश किया है। इस वर्ष शिक्षा के लिए कुल 1.45 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, यह आवंटन देश की मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने और भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि शिक्षा पर खर्च को केवल व्यय नहीं,

स्कूली शिक्षा के लिए 78 हजार करोड़

स्कूली शिक्षा के लिए करीब 78,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। इस फंड का बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को सुधारने, नए कक्षों के निर्माण, पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट क्लासरूम

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही, समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों की सीखने की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार लाया जाए।

शोध के लिए फंड बढ़ाया

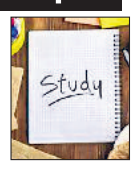

बजट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी कर इसे 8,000 करोड़ रुपये किया है। इससे विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल शिक्षा और तकनीक

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने, ई-लर्निंग कंटेंट को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने और ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स को मान्यता देने की दिशा में यह राशि खर्च की जाएगी।

एआई के लिए भी प्रावधान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में शिक्षा के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन केंद्रों के लिए शुरुआती चरण में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

कौशल विकास व व्यावसायिक शिक्षा पर जोर

जट 2026-27 में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 12,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट सेंटरों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने और उनके पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की योजना है। सरकार का मानना है कि केवल डिग्री आधारित शिक्षा से रोजगार की समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए स्कूल स्तर से ही स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण

बजट में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा। शिक्षा ऋण को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने ब्याज सब्सिडी योजना के तहत अतिरिक्त 2,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जिससे उच्च शिक्षा हासिल करना गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए आसान होगा।

"बजट 'भविष्य के लिए तैयार भारत' के निर्माण के उद्देश्य से बनाया गया है और इससे निर्यात एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में विनिर्माण, सेवाओं, निर्यात, महिलाओं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरों, पशुपालन और नई प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया भारत में स्थित डेटा केंद्रों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को 'क्लाउड' सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव रखा गया है।" _ पीयूष गोयल, उद्योग मंत्री

4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आत्मनिर्भर भारत कोष में

तेजी आएगी : वित्त मंत्री ने की 10,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा

एमएसएमई सेक्टर को बनाएंगे चैंपियन

लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा

2000 करोड़ — आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त डाले जाएंगे

7 लाख करोड़ — ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को धनराशि उपलब्धता

टियर 2 और 3 — शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का कैडर तैयार किया जाएगा

'कॉर्पोरेट मित्र': बजट में सरकार 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार करने के लिए छोटे कोर्स शुरू करने में मदद करेगी। ये 'कॉर्पोरेट मित्र' ऐसे सलाहकार या सेवा प्रदाता होंगे जो एमएसएमईएस को नियमों के पालन , मानव संसाधन और कानूनी जरूरतों में सहायता करेंगे।

यूं टिकी रहीं निगाहें...

भाषा ▶▶ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं।

उन्होंने कहा कि बजट की रीति-नीति तीन कर्तव्यों पर आधारित है जिसमें आर्थिक वृद्धि को तेज और स्थायी बनाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण तथा सबका साथ, सबका विकास। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इक्विटी समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेड्स मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी का लेनदेन ट्रेड्स मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जीईएम को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सस्ता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

पेशेवर समर्थन के तहत आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसी पेशेवर संस्थाओं को संक्षिप्त मॉड्यूलर पाठ्यक्रम तैयार करने और दूसरे एवं तीसरे दर्जे के शहरों में 'कॉरपोरेट मित्र' का एक कैडर तैयार करने के लिए व्यावहारिक साधन विकसित किए जाएंगे।

महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए 'शी मार्ट' स्थापित किए जाएंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 'लखपति दीदी योजना' की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकानें स्थापित की जाएंगी। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए ''उद्यमों के मालिक'' बनने की दिशा में ''अगला कदम'' बताया। सीतारमण ने कहा, '' लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को ऋण-आधारित आजीविका से उद्यमों की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा, '' स्वयं सहायता उद्यमी - शी मार्ट को उन्नत एवं नवोन्मेषी वित्त साधनों के माध्यम से संकुल-स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकान के रूप में स्थापित किया जाएगा।'' लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है।

क्या है शी-मार्ट योजना

- महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सहायता देना
- महिलाओं को बाजार तक डायरेक्ट जोड़ने में मदद करना।
- आसानी से लोन और फाइनेंस कराना
- खुद के उत्पादों को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना
- यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। साथ ही कौशल विकास और व्यवसायिक सहायता देगी. महिलाओं को अपने व्यवसाय को स्थिर और सफल बनाने के लिए सपोर्ट, ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस भी दिया जाएगा।

शेयरों की पुनर्खरीद पर अब लगेगा 'पूंजीगत लाभ कर'

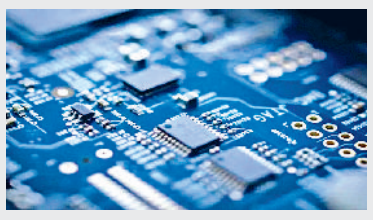

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए शेयरों की पुनर्खरीद (बायबैक) से होने वाली आय पर अब 'पूंजीगत लाभ कर' लगाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने वस्तु वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को भी 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को अब 'अंतिम कर' बनाया जाएगा और इसकी दर को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।

कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव

सरकार ने रविवार को श्रम-गहन कपड़ा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की और 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। अपने बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''श्रम-गहन कपड़ा क्षेत्र के लिए, मैं पांच उप-खंड के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूं।'' इन पांच उप-खंड के तहत, उन्होंने रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए 'नेशनल फाइबर स्कीम' (राष्ट्रीय धागा योजना) की घोषणा की।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' का ध्यान पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी (बौद्धिक संपदा) के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन पर होगा। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक विशिष्ट और स्वायत्त प्रभाग है। इसका उद्देश्य देश में एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर और 'डिस्प्ले' पारिस्थितिकी तंत्र का विनिर्माण करना है। सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में महत्वपूर्ण खनिज सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' सरकार का तीसरा 'कर्तव्य' है।

उम्मीद

'नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड' की स्थापना की जाएगी

खादी-हथकरघा सशक्तीकरण और टेक्सटाइल उद्योग में नई पहल

10 लाख रुपये

कूरियर निर्यात की सीमा को हटाने से ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन

मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की तैयारी

सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा, मैं 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। वे तकनीकी वस्त्र में मूल्यवर्धन करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करेगा।

टेक्स-इको इनिशिएटिव जल्द ही शुरू होगा

सीतारमण ने विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ कपड़ा एवं परिधानों को बढ़ावा देने के लिए एक 'टेक्स-इको इनिशिएटिव' शुरू होगा। सरकार ने उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गठजोड़ के माध्यम से वस्त्र दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और उन्नयन करने के लिए 'समर्थ 2.0' का भी प्रस्ताव दिया।

एसटीटी बढ़ोतरी का वित्त मंत्री ने किया बचाव

सट्टे से छोटे निवेशकों को हो रहा था नुकसान

नई दिल्ली। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में की गई तीखी बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि डेरिवेटिव्स में सट्टा गतिविधियों के कारण छोटे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है और सरकार इस पर चुप नहीं रह सकती। हालांकि, बाजारों में इस कदम के बाद ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों में गिरावट देखी गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि बढ़ी हुई लागत दुनिया के सबसे व्यस्त एफएंडओ बाजारों में से एक में गतिविधि को ठंडा कर सकती है। केंद्रीय बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को दोगुने से अधिक कर दिया गया है और ऑप्शंस पर कर 50% तक बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने और प्रणालीगत जोखिम (सिस्टमिक रिस्क) को प्रबंधित करने के लिए उठाया गया है। इन घोषणाओं के बाद रविवार के विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र में ब्रोकरेज और एक्सचेंज कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई।

ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों में गिरावट

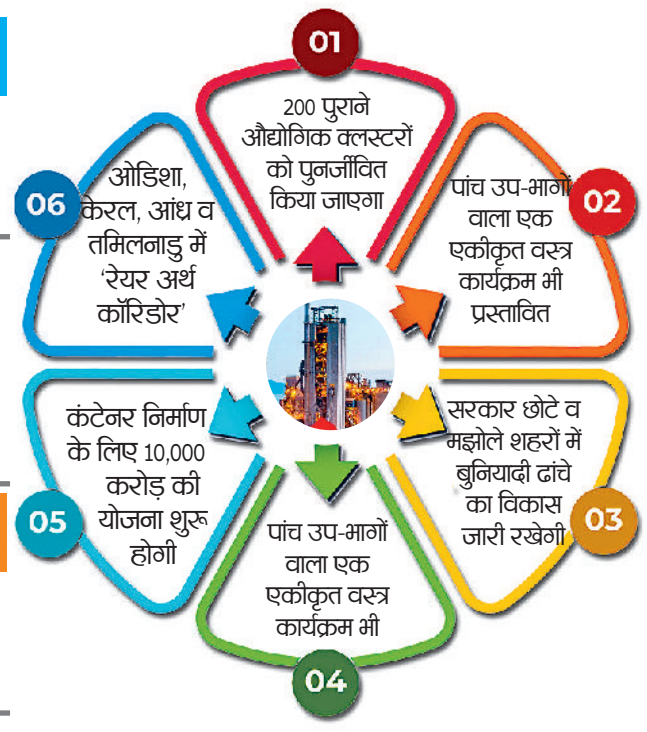

डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर बढ़े कर का बाजार पर तुरंत असर पड़ा। रविवार के विशेष ट्रेडिंग सत्र में बीएसई, ग्रो और एंजेल वन के शेयरों में 13.5% तक की गिरावट आई। दिन के अंत तक बीएसई के शेयर 8% और एंजेल वन के शेयर 8.6% गिर गए। आशंका है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर बढ़ी लागत से उस सेगमेंट में गतिविधि कम हो सकती है, जो एक्सचेंज और रिटेल ब्रोकरेज कंपनियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बन चुका है। इक्विरस सिक्योरिटीज के सीईओ विशद तुराखिया के अनुसार, मौजूदा वित्तवर्ष की पहली छमाही में बीएसई की 60% आय इक्विटी डेरिवेटिव्स से आई, जबकि एंजेल वन की 9 महीनों की अवधि में 75% ब्रोकिंग आय एफएंडओ से रही। नुवामा वेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, जहां एसेट सर्विसेज से लगभग 23% आय डेरिवेटिव गतिविधि से जुड़ी है।

विदेशी निवेशकों पर असर

एसटीटी में बढ़ोतरी का अल्पकालिक प्रभाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह पर भी पड़ सकता है, खासकर डेरिवेटिव-आधारित और हाई-फ्रीक्वेंसी रणनीतियों में। जनवरी 2026 में ही एफआईपी ने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की इक्विटी निकासी की थी, जो वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और मुद्रा दबाव को दर्शाता है। बढ़ी हुई लेन-देन लागत से अल्पकाल में विदेशी निवेशकों की कर-पश्चात रिटर्न और कम हो सकता है।

'सट्टे' पर नजर

सीतारमण ने बजट भाषण के बाद कहा कि हम केवल फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट को छू रहे हैं। कहीं और लेन-देन लागत नहीं बढ़ाई गई है। सट्टा अत्यधिक जोखिमपूर्ण होता है और सीमित संसाधनों वाले कई लोगों को भारी नुकसान होता है। एसटीटी में यह मामूली वृद्धि केवल अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए है। हम बाजार गतिविधि का सम्मान करते हैं, लेकिन छोटे निवेशकों के नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाजार के बाकी हिस्से का नियमन बाजार नियामक के अधीन है। संसद में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं प्रस्ताव करती हूं कि फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जाए। ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर एसटीटी को क्रमश: 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% किया जाए।' यह वृद्धि पूंजी बाजार के एफएंडओ सेगमेंट में उचित सुधार लाने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उद्देश्य से की गई है।

लिथियम-आयन सेल के कच्चे माल पर सीमा शुल्क माफ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के वार्षिक बजट में बैटरी भंडारण के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट के विस्तार की घोषणा की। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सीएनजी में मिश्रित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा, /"मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी जाने वाली मूल सीमाशुल्क छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही मैं सौर कांच के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटी मोनेट के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।/"

4000 ई-बस का प्रावधान

पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में कहा कि मैं दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।' बजट में भारत में निर्मित वस्तुओं या नगण्य आयात वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

बजट में खास

- 01 निर्माण को बड़ा पुश
- 02 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को समर्थन
- 03 व्यापार में सुगमता बढ़ेगी
- 04 एक्सपोर्ट व विदेशी स्तर पर प्रतिस्पर्धा
- 05 बुनियादी ढांचा व कनेक्टिविटी
- 06 टेक्नोलॉजी व डिजिटल बिजनेस
- 07 वित्त और टैक्स प्रोत्साहन

टेक्सटाइल उद्यमियों में खुशी का माहौल

पानीपत। केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल उद्योग को केंद्रीय करते हुए की गई घोषणाओं के बाद पानीपत के टेक्सटाइल उद्यमियों में खुशी का माहौल है। टेक्सटाइल उद्यमियों ने मोदी सरकार के बजट को दूरदर्शी व रोजगार परक बताया। वहीं, टेक्सटाइल उद्योगपतियों ने विश्वास जताया कि मोदी सरकार के बजट से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीदें जगी है। हैंडलूम एक्सपोर्टर प्रामोशन काउंसिल (हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद) के अध्यक्ष ललित गोयल ने मोदी सरकार के बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए बजट को दूरदर्शी और रोजगार केंद्रित बजट करार दिया। गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार का बजट टेक्सटाइल के सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के नेतृत्व वाले निर्यात विकास को मजबूत करते हुए भारत के हैंडलूम और कपड़ा टेक्नोलॉजी तंत्र को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सकरार का बजट, इंटरनेशन मार्किट में टेक्सटाइल उत्पादों को गतिशीलता प्रदान करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका और विश्व स्तर पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ हैंडलूम और कपड़ा जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के विस्तार को सही ढंग से पूर्ति करेगा। वहीं, गोयल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए अपनाए गए एकीकृत दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसमें फाइबर आत्मनिर्भरता, पारंपरिक समूहों का आधुनिकीकरण, स्थिरता और कौशल विकास शामिल है। राष्ट्रीय फाइबर मिशन, नेशनल हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल, मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल और समर्थ 2.0 के तहत केंद्रित कौशल जैसी पहल उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी और बुनकरों और कारीगरों की आय में सुधार करते हुए हैंडलूम और कपड़ा निर्यातकों को इंटरनेशल मार्किट की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कपडे के उत्पादों के लिए विस्तारित निर्यात समयसीमा, विश्वास-आधारित सीमा शुल्क सुविधा, कंटेनर विनिर्माण और समर्पित माल गलियारों के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स और कूरियर निर्यात पर 10 लाख रुपये प्रति खेप की मौजूदा मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने सहित निर्यात-सक्षम सुधारों की भी सराहना की।

सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्यमियों को

टेक्सटाइल एक्सपोर्टर राकेश जैन ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना चुनौतीपूर्ण तरीके से की जाएगी। टेक्सटाइल के सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को बहुत फायदा होगा। वहीं पानीपत के उद्यमियों को कॉमन बॉयलर, जेडएलडी और पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्यमियों को होगा। वर्तमान में पानीपत का हथकरघा उद्योग प्रिंटेड बेडशीट व मिंक कंबल उद्योग में चीन को विश्व स्तर पर कड़ी टक्कर दे रहा है। हैंडीक्राफ्ट और कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित होगी।

टेक्सटाइल उद्योग पर विशेष ध्यान दिया

हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पानीपत चैप्टर के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा कि केंद्रीय बजट में सुक्ष्म, लघु और मध्यम टेक्सटाइल उद्योग को व्यापक समर्थन प्रदान करके टेक्सटाइल उद्योग पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये की घोषणा, कंटेनरों के निर्माण, मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 10,000 करोड़ रुपये की घोषणा, रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने, उद्योग में सुधार के लिए नई योजना राष्ट्रीय हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम शुरू करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देने से निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में उत्पादन, रोजगार-निर्यात पर फोकस

बहादुरगढ़। केंद्रीय बजट पर चर्चा करते कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज सदस्य।

बहादुरगढ़। औद्योगिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज का मानना है कि केंद्रीय बजट में उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने पर सीधा फोकस रखा गया है। खासतौर पर एमएसएमई के लिए वित्तीय सहयोग से निवेश और रोजगार दोनों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग के अनुसार बजट में युवा, किसान, गरीब, व्यापारी, एमएसएमई और आम आदमी के हितों को ध्यान में रखा गया है। सरकार की दूरदृष्टी नीतियों के कारण भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरेगा। उन्होंने बजट में एमएसएमई को 10 हजार करोड़ का फंड देने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी। कोबी महासचिव प्रदीप कौल के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में एसएमई ग्रोथ फंड और आत्मनिर्भर भारत फंड में अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य कदम है। टैक्स एवं अनुपालन सुधारों को लेकर बजट में ईस ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया गया है।

लघु व मध्यम उद्योग को फायदा

कोबी कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल के अनुसार बजट में कारपोरेट मित्र व्यवस्था के जरिये एमएसएमई को तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन देने की पहल की गई है। छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान और कार्यशील पूंजी की समस्या से राहत देने के लिए ट्रेड्स (ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्लेटफार्म का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है। टीडीएस/टीसीएस से जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डी-क्रिमिनलाइजेशन से व्यापारियों और उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और कैश फ्लो में सुधार आएगा।

"केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसंरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। गडकरी ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना बनाने के लिए एक निर्णायक कदम रेखांकित किया गया है। -नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री"

10,000 करोड़ पांच साल में कंटेनर निर्माण की योजना का प्रस्ताव

सरकार ने देश के हर क्षेत्र को गति देने का किया ऐलान

बनेंगे सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

इनका लक्ष्य बड़े महानगरों के बीच की दूरी घटाना और विकास को नई रफ्तार देना

ये सात प्राइम रेल कोरिडोर्स होंगी जो सात रेल रूट्स को कनेक्ट करेंगी। इन पर सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे इन शहरों के बीच रेल सफर की आम समय सीमा घट जाएगी।

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते समय भारतीय रेलवे को लेकर बड़ा एलान किया है। इसमें देश में हाई स्पीड ट्रेन के सपने को विस्तार देते हुए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोर्स का लक्ष्य न केवल बड़े महानगरों के बीच की दूरी को कम करना है बल्कि इससे देश की विकास को एक नया रफ्तार देना है। 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से भविष्य में देश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह देश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इन कॉरिडोर्स का लक्ष्य न केवल बड़े महानगरों के बीच की दूरी को कम करना है बल्कि इससे देश की विकास को एक नया रफ्तार देना है। ये रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट यह दर्शाने का काम करता है कि भारत अब तकनीक और रफ्तार के मामले में दुनिया के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आने वाले दशक में ये कॉरिडोर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे।

इन रूटों पर हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा

- ⏭ **दिल्ली से वाराणसी:** यह उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर होगा
- ⏭ **वाराणसी से सिलीगुड़ी:** यह पूर्वांचल को उत्तर-पूर्व (नॉर्थ-ईस्ट) के प्रवेश द्वार से जोड़ेगा।
- **मुंबई से पुणे:** महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच की दूरी कम होगी।
- ⏭ **पुणे से हैदराबाद:** दक्षिण और पश्चिम भारत के बीच बेहतर संपर्क।
- ⏭ **हैदराबाद से बेंगलुरु:** दो प्रमुख टेक हब के बीच तेज कनेक्टिविटी।
- ⏭ **हैदराबाद से चेन्नई:** दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना।
- ⏭ **चेन्नई से बेंगलुरु:** व्यापारिक और पेशेवर आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण।

क्यों खास है यह कदम?

वर्तमान में भारत में एकमात्र हाई-स्पीड रेल परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद) पर काम चल रहा है। 7 नए कॉरिडोर की घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार अब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी को पैन-इंडिया (अखिल भारतीय) स्तर पर ले जाना चाहती है। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट और रोजगार के अवसरों में भारी उछाल आने की संभावना है।

बुजुर्गों को रेल यात्रा में नहीं मिली छूट बाकी सब यथावत

भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं की गई जिससे बुजुर्गों को निराशा हाथ लगी।

दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर

यह लगभग 813 किलोमीटर लंबा होने की उम्मीद है। यह रूट दिल्ली से शुरू होकर नोएडा, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों को कवर करते हुए वाराणसी पहुंचेगा।

वाराणसी पर विशेष फोकस

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दो कॉरिडोर (दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी) से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनाने की भी घोषणा की गई है।

बजट आवंटन

सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए कुल 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन रेल परियोजनाओं पर खर्च होगा।

पर्यावरण और गति

इन ट्रेनों की गति 320-350 किमी/घंटा तक हो सकती है। इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके।

सदन में जाते अश्विनी वैष्णव

सीमा शुल्क में कमी

- **महत्वपूर्ण खनिज** : मोनाजाइट पर सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा** : सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण में प्रयुक्त निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर भी शून्य शुल्क लगेगा।
- **परमाणु ऊर्जा** : परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर शून्य किया गया है। यही छूट नियंत्रण एवं प्रोटेक्टर एब्जॉर्बर रॉड तथा बर्नेबल एब्जॉर्बर रॉड पर भी लागू होगी। प्रोजेक्ट इम्पोर्ट रेगुलेशंस, 1986 के अनुरूप 30 सितंबर 2035 तक कस्टम हाउस में पंजीकृत निर्दिष्ट परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित वस्तुओं पर भी शून्य शुल्क लगेगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स** : माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया गया है।
- **नागरिक उड्डयन** : विमान निर्माण के लिए इंजन सहित आवश्यक घटकों व पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया।
- **सीमा शुल्क में वृद्धि**

रसायन: पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है।

- **छाते और उनसे जुड़े पुर्जे** : उद्यान छातों को छोड़कर अन्य छातों पर वर्तमान में 20% सीमा शुल्क लगता है। यह या तो 20% ही रहेगा या प्रति पीस 60 रुपये जो भी अधिक हो लगाया जाएगा। इसी प्रकार पुर्जों, ट्रिमिंग और अन्य सहायक वस्तुओं पर वर्तमान 10% सीमा शुल्क या प्रति किलोग्राम 25 रुपये में जो भी अधिक हो लागू रहेगा।

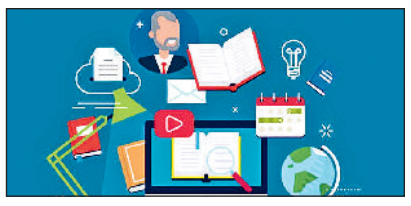

बनेगा राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश भर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों समेत सभी अहम जगहों के बारे में जानकारी को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए एक 'राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड' बनाने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 'पारिस्थितिकीय तौर पर टिकाऊ' पर्वतीय मार्गों को विकसित करने और एक 'राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार संस्थान' (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी) बनाने का भी प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा विनिमय से कमाई करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में पर्यटन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बुद्ध सर्किट

नई दिल्ली । सीतारमण ने इस बार बजट में पर्यटन पर काफी फोकस रखा गया है और मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कॉरिडोर का ऐलान किया है। कॉरिडोर का नाम रखा गया है- बौद्ध सर्किट जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर योजना के तहत मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा, 'सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना शुरू करेगी ताकि मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जा सके। सरकार पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का विकास करेगी।

15 पुरातात्विक स्थलों होंगे जीवंत तरीके से विकसित

20 टूरिस्ट साइट्स और इको-टूरिज्म को बढ़ावा

10 हजार गाइड्स के लिए विशेष कोर्स

शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताया और कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और टियर तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं... शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। बजट दस्तावेज के अनुसार, यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर)... बेंगलुरु, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-ईरोड-तिरुप्पुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

परिवहन पर सबसे ज्यादा खर्च करीब 5.98 लाख करोड़ रुपये

खर्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो परिवहन सेक्टर सबसे ऊपर है, जहां करीब 5.98 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ रुपये और गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह खर्च ग्रामीण इलाकों में सड़क, आवास, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

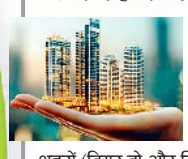

एसईजेड से घरेलू बाजार में रियायती शुल्क पर बिक्री के लिए विशेष एकमुश्त उपाय का प्रस्ताव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में रियायती शुल्क दरों पर बिक्री की सुविधा के लिए एक विशेष एकमुश्त उपाय का प्रस्ताव रखा। यह उद्योग जगत की एक पुरानी मांग थी, क्योंकि अमेरिका में उच्च शुल्क के कारण एसईजेड इकाइयों को अपनी क्षमता के उपयोग से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ''वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण एसईजेड में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमता के उपयोग के संबंध में उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के लिए, मैं एक विशेष एकमुश्त उपाय के रूप में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा डीटीए (घरेलू बाजार) में रियायती शुल्क दरों पर बिक्री की सुविधा देने का प्रस्ताव करती हूं।''

20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण (सीआईई) के घरेलू निर्माण को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) संचालित करेगी, जिसकी शुरुआत ओडिशा में एनडब्ल्यू-5 से होगी।

किसे क्या मिला?

निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का भी उन्होंने बजट में प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं।

आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु को बर्डिंग ट्रेल का तोहफा

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्डिंग ट्रेल बनाने का एलान किया। बता दें कि बर्डिंग ट्रेल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक विशेष रूप से चिन्हित रास्ता होता है, जिसे पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने, पहचानने और अध्ययन करने के लिए विकसित किया जाता है। ये मार्ग आमतौर पर ग्रामीण, तटीय या जंगली क्षेत्रों में बनाया जाता है।

आवास ऋण: लाभांश आय पर ब्याज खर्च की कटौती समाप्त

नई दिल्ली (भाषा)। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट की स्थापना करेंगे

⏭ इससे सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों को बाजार में चढ़ाने की योजना

नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को बाजार में चढ़ाने या मौद्रीकरण में तेजी लाने के लिए समर्पित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) की स्थापना का बजट में रविवार को प्रस्ताव रखा। रीट निवेश के ऐसे साधन हैं जो आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति के मालिक होते हैं या उसका संचालन करते हैं। इससे निवेशकों को सीधे संपत्ति खरीदे बिना उत्पन्न आय का एक हिस्सा अर्जित करने में मदद मिलती है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '' पिछले कुछ वर्षों में, रियल एस्टेट निवेश (रीट) परिसंपत्ति मौद्रीकरण के एक सफल साधन के रूप में उभरे हैं।

नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ के प्रोत्साहन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को नगर निगम द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के तहत आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पुनर्गठन की भी घोषणा की। मंत्री ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग' पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया।

बजट में रेलवे को 2.77 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए

नई रेल लाइन बिछेंगी, कोच खरीदे जाएंगे

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के 2,52,000 करोड़ की तुलना में 10.25 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, रेलवे को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस बढ़े हुए आवंटन से रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

पेंशन खर्च में बढ़ोतरी

रेलवे के कुल खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन पर जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर 58,844.07 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं, 2024-25 में रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपए की कमाई और 3,32,440.64 करोड़ रुपए का खर्च किया था। अधिकारियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के वास्तविक आंकड़े वर्ष समाप्त होने के बाद सामने आएंगे, हालांकि अब तक कमाई और खर्च अनुमान के अनुरूप ही बने हुए हैं।

कमाई-खर्च और सरकारी सहायता की जरूरत

बजट दस्तावेजों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे वर्ष के अंत में 3,547.32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय रहने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा कमाई इतनी पर्याप्त नहीं है कि उससे बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति निर्माण और नए कार्यों को पूरी तरह वित्तपोषित किया जा सके। इसी कारण नई लाइन बिछाने, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण जैसी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता दी जाती है।

कहां कितना होगा खर्च

⏭ नई रेल लाइनों के लिए	36,721.55 करोड़
⏭ नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तन	4,600 करोड़
⏭ लाइन दोहरीकरण	37,750 करोड़ रुपए
⏭ रोलिंग स्टॉक (लोको, वैगन आदि)	52,108.73 करोड़
⏭ सिग्नलिंग और दूरसंचार	7,500 करोड़

इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

रेल मंत्रालय को मिले 2,77,830 करोड़ रुपए के आवंटन का बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इन निवेशों से रेलवे नेटवर्क की क्षमता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

वन और रेल विभाग के समन्वित प्रयासों से ट्रेन दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत की घटनाएं कम हुईं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल वन विभाग और रेलवे के समन्वित प्रयासों व घुसपैठ पहचान प्रणाली (आईडीएस) के शुरू होने से पिछले दो साल में उत्तरी बंगाल के वन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली रेल पटरियों को पार करते समय हाथियों की मौत की कोई घटना नहीं हुई। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल पटरियां बुक्सा बाघ अभयारण्य, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और चापरामारी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर वन विभाग व रेलवे की संयुक्त निगरानी और आईडीएस के कारण पिछले दो साल में रेल की चपेट में आने से हाथियों की मौत की कोई घटना नहीं हुई।

अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा

डॉ. राजेश कुमार

मदवि के अर्थशास्त्र विभाग के अर्थशास्त्री डॉ. राजेश कुमार ने हालिया बजट को कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उनके अनुसार, यह बजट न केवल अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वित्तीय मजबूती, राजकोषीय घाटे में कमी डॉ. कुमार ने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। पिछला राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत और नया लक्ष्य 4.3 प्रतिशत है। डॉ. राजेश के अनुसार, घाटे में कमी दर्शाती है कि सरकार खर्चों और राजस्व के बीच बेहतर संतुलन बना रही है, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। यूनिवर्सिटी टाउन शिप शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, बजट में यूनिवर्सिटी टाउनशिप के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

सीएम ने बजट को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया

केंद्रीय बजट से औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा नया विस्तार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ चंडीगढ़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए आम बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को समर्पित है। उन्होने कहा कि इस समावेशी बजट से हरियाणा में औद्योगिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायो फार्मा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं खेल क्षेत्र को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पंचकूला में केंद्रीय बजट के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इससे पूर्व उन्होने स्क्रीन के माध्यम से केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इस बजट के 3 मुख्य विजन हैं। रफ्तार का अर्थ है- प्रॉडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, क्षमता -लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें और सबका साथ- हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों।

चंडीगढ़। पंचकूला में केंद्रीय बजट पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते सीएम नायब सिंह सैनी। फोटो : हरिभूमि

किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा बजट

सीएम ने कहा कि यह सर्वसमावेशी बजट किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। हरियाणा के लिए बजट को विशेष रूप से उत्साहजनक बताते हुए कहा कि खेलो इंडिया मिशन पर जोर हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे कि राखीगढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा।

स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा हरियाणा : सीएम

एआई शिखर सम्मेलन में 4 देशों के वक्ताओं ने लिया भाग

हरियाणा बनेगा एआई नवाचार का केंद्र, विश्व बैंक देगा 470 करोड़ रुपये की मदद

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के संकल्प को साकार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोकल एआई रियल इम्पैक्ट केवल एक विषय नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसमें वैश्विक सोच को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित टीआईई एआई शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दि इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन भविष्य की तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच है। इस शिखर सम्मेलन में 4 देशों, 11 राज्यों के वक्ताओं ने भाग लिया। इसकी थीम ग्लोकल एआई रियल इम्पैक्ट रखा गया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्रभावशाली और सार्थक परिणाम उत्पन्न करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 470 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

विकसित भारत का रोडमैप है केंद्रीय बजट

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान से हरियाणा को बड़ा फायदा होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट दरअसल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का दूरदर्शी और ऐतिहासिक रोडमैप भी है। अंत्योदय की भावना से प्रेरित इस बजट के तीन स्पष्ट विजन हैं। रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। रफ्तार यानि उत्पादकता बढ़ा कर आर्थिक विकास की गति तेज करना। क्षमता यानि देश की प्रगति में भागीदारी के लिए लोगों की प्रतिभा और क्षमता निखारना। 'सबका साथ, सबका विकास' प्रधानमंत्री का सुशासन का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है हर किसी के पास कमाई के पर्याप्त अवसर और संसाधन हों। इसलिए तात्कालिक लोकप्रियता की आकांक्षा से मुक्त नया बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का दस्तावेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान से स्पष्ट है कि भारत का इरादा आयात घटाने से आगे निर्यात बढ़ाने का है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहना उसकी मजबूती को ही दर्शाता है। ऐसे समय जबकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिचकोल खा रही हैं, भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहना मोदी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन का भी परिणाम है। ऊर्जा सुरक्षा भविष्य की प्रगति की कुंजी बननेवाली है। इसलिए उस पर भी फोकस रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में साढ़े 12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और सिटी इकॉनोमिक रीजन का विकास खासकर हरियाणा जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रित औद्योगिक राज्य की प्रगति को नयी उड़ान देगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से भी लाभार्थी राज्यों में हरियाणा अग्रणी रहेगा। सेमीकंडक्टर हब के लिए 40 हजार करोड़ रुपये और बायोफार्मा सेक्टर पर फोकस भारत को प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनायेगा, तो दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, देश में बड़े टैक्सटाईल पार्क और पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने से इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा।

शिष्टाचार मुलाकात

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नई दिल्ली में पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट कर बधाई दी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।

प्रदेश में नए अस्पताल खोले और अपग्रेड किए जा रहे : आरती राव

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल

खोले जा रहे हैं तथा अपग्रेड किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने तथा दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बेड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सभी पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

बजट पर आप नेता ढांडा की तीखी प्रतिक्रिया

खेती को कमजोर और हरियाणा को पीछे करने वाला केंद्रीय बजट

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ चंडीगढ़

हरियाणा के लिए निराशा अन्याय और भेदभाव का दस्तावेज़ बताया

आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आम बजट को देश के किसानों, खेती-बाड़ी और हरियाणा के लिए निराशा, अन्याय और भेदभाव का दस्तावेज़ है। यह बजट साफ दिखाता है कि मोदी सरकार की नीयत में न किसान है, न खेती और न ही हरियाणा। बजट के बड़े-बड़े दावों के पीछे सच्चाई यह है कि अन्नदाता को एक बार फिर धोखा दिया गया है। ढांडा ने कहा कि बजट में कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए केवल 1.62 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि 2025-26 में यह राशि 1.71 लाख करोड़ थी। यानी खेती के बजट में सीधे तौर पर 6,985 करोड़ की कटौती की गई है। सरकार इसे भले ही "री-एलाइनमेंट" कहे, लेकिन हकीकत में यह किसानों पर सीधा हमला है। यह लगातार दूसरा साल है जब कृषि बजट को दबाया गया है।

सूरजकुंड मेले को मिलेगा डिजिटल प्लेटफार्म ऑनलाइन बेच सकेंगे हस्तशिल्प उत्पाद

फरीदाबाद। हरियाणा से विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस वर्ष एक नए डिजिटल अवतार में नजर आने वाला है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय शिल्पकारों के हुनर को सात समंदर पार पहुंचाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। पर्यटन र्यटन मंत्रालय के सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्ण ने बताया मेले के 15 दिनों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि साल के 365 दिन अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच सकेंगे। इसका मकसद शिल्पकारों के हुनर को वैश्विक स्तर पर ले जाना है।

बजट पर प्रतिक्रिया

प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी

मोदी सरकार का यह बजट हरियाणा के विकास को नई गति देगा और आने वाले समय में इन्फ्रा, कृषि और रोजगार पर बड़ा फोकस रहेगा। यह बजट विकसित भारत की यात्रा को और तेज करेगा। यह युवा शक्ति बजट है। युवाओं की सोच और सपने बजट में शामिल हैं।
- मोहन लाल बडौली, अध्यक्ष, हरियाणा भाजपा

जनता की अपेक्षाओं से परे बजट

बजट ज़मीनी हकीकत से कटा हुआ और जनहित से दूर है। आम आदमी, किसान और ग्रामीण भारत की अनदेखी की गई है। बजट में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कर्जमाफी, पानी-बिजली संकट के लिए कोई ठोस राहत पैकेज नहीं। मनरेगा जैसी योजनाओं में पहले से कटौती कर दी गई है। **-राव नरेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष**

हरियाणा के खाली हाथ, सौतेला बर्ताव

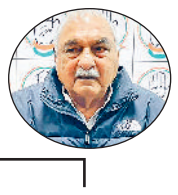

केंद्रीय बजट को हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करार देते हुए इसे पूरी तरह खोखला और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा को खाली हाथ रखा गया है, जबकि आम आदमी, किसान, मजदूर और ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली।
-भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

हरियाणा के लिए कुछ नहीं

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अब तक का सबसे निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के मद्देनजर केवल साउथ इंडिया पर फोकस किया है, जबकि हरियाणा के लिए इसमें कुछ नहीं है।
-दुष्यंत चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री

राशिफल

मेष — मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं।

वृष — आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन — किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। सुस्वादु खानपान में रुचि रहेगी।

कर्क — जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। वाणी में सौम्यता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

सिंह — जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दें।

कन्या — पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक या शोधादि कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें।

तुला — मन प्रसन्न रहेगा। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। कुटुम्ब के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें।

वृश्चिक — मन में नकारात्मक विचारों से बचें। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे।

धनु — आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति रहेगी। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। घर-परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं।

मकर — क्रोध से बचें। बातचीत में संयत रहें। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। पिता से धन मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

कुंभ — मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। अनियोजित खर्च बढ़ेंगे। माता का सहयोग मिलेगा।

मीन — पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

सूचना

चौ. लखीराम आर्य जगन्नाथ आश्रम के त्रिवार्षिक चुनाव 01.03.2026 को प्रस्तावित है। समस्त कार्यक्रम आश्रम की वेबसाईट w.w.w.lakhiramanathaley.org पर है।

हस्ता/- प्रधान

सार्वजनिक सूचना

ICICI Home Finance | पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई 400059
शाखा पता : प्रथम तल, जुबिन टावर, आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ में, जी.टी. रोड, पानीपत-132103
शाखा पता : प्रथम तल, नं. 159/20, सुधा कॉम्पलैक्स, एटलस रोड, निकट सुभाष चौक, सोनीपत-131001
शाखा पता : प्लॉट नं. 45-46, प्रथम तल, सत करतार कॉम्पलैक्स, 45, वजीर चंद कॉलोनी, मुगल कैनाल फाउंटेन चौक के सामने, करनाल-132001
शाखा पता : एससीओ 154, प्रथम तल, रेड स्क्वेयर मार्केट, यूई-1, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, हिसार-125001

निम्नलिखित कर्जदार आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफसी") से उनके द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान करने में चूककर्ता बन चुके हैं और ऋणों को नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। प्रतिभूति हित अधिनियम-2002 के प्रवर्तन और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रत्याभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पतों पर उनको एक नोटिस जारी किया गया था, यद्यपि इसकी तामील नहीं हो पाई और इसलिए उनको इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम/ (ऋण अकाउंट नम्बर) और पता	प्रत्याभूत परिसम्पत्ति / प्रवर्तित की जानी परिसम्पत्ति का सम्पत्ति पता	भेजे गये नोटिस की तिथि / नोटिस की तिथि के अनुसार बकाया	एनपीए तिथि
1.	ललित नारायण (कर्जदार), प्रेम लता (सह-कर्जदार), 289, वार्ड 19, गोहाना गोहाना-131301 हरियाणा LHPNP00001400013.	प्लॉट माप 30.56 वर्ग गज अर्थात मरला जो गोझाना के राजस्व सम्पदा के अंदर, आबादी वार्ड नं. 18, गांधी नगर के रूप में जानी जाती तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में स्थित खेवट नं. 4384/4169 खतौनी नं. 4805, रेक्ट. नं. 235, किल्ला नं. 23(7-12) में निहित भूमि माप 07 कनाल 12 मरला में से हिस्सा 1/152. सीमाएं :- उत्तर : 25' रामकुमार की सम्पत्ति, दक्षिण : 25' दीवान सिंह की सम्पत्ति, पूर्व : 11' रास्ता (23' चौड़ा), पश्चिम : 11' नरेन्द्र बंसल की सम्पत्ति।	12-01-2026 रु. 8,40,203/-	03/01/2026
2.	रेखा पत्नी मनदीप (कर्जदार), मनदीप कादुयान (सह-कर्जदार), मनदीप कादुयान (सह-कर्जदार), सतनारायण पुत्र मामचंद्र (सह-कर्जदार), गांव भुरी (96) राजपुर जिला सोनीपत-131100 LHSNP00001544581.	सतनारायण के पक्ष में दस्तावेज नं. 3636 दिनांक 31.03.2017 के अनुरूप जमाबंदी वर्ष 2011-12 के अनुसार वाका रकबा ग्राम/गांव भुरी तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत में स्थित खेवट नं. 202 खाता नं. 277, किल्ला नं. 26//15/2/2/2/1(1-13) में निहित भूमि माप 1के13एम में से 21/33 हिस्सा जो 1के-1एम अर्थात सम्पत्ति माप 633 वर्गगज के सभी भाग व हिस्से, सीमाएं :- उत्तर : 83 फीट ईश्वर का मकान, दक्षिण : 136 फीट निजी रास्ता राजेन्द्र, पूर्व : 52 फीट राजेश, पश्चिम : 75 फीट रोड।	28-01-2026 रु. 24,14,702/-	03/01/2026
3.	जसविन्दर सिंह पुत्र राम चंद (कर्जदार), कुलवंत कौर पत्नी जसविन्दर सिंह (सह-कर्जदार), मकान नं. 112/13, सेक्टर-13, जंडवाला मोहल्ला सिरसा, हरियाणा-125056 मोबाइल नं. 9354958406 LHSIR00001324029.	कुलवंत कौर के पक्ष में दस्तावेज नम्बर 6933 दिनांक 24.01.2017 के अनुरूप खन्ना कॉलोनी सिरसा गांव खारपुर तहसील व जिला सिरसा में स्थित भूमि 200 वर्गगज का 1/2 हिस्सा जो सम्पत्ति/प्लॉट नं. 431 माप 100 वर्गगज (उत्तर) है, के सभी भाग व हिस्से। सीमाएं :- उत्तर : प्लॉट नं. 432, 60 फीट, दक्षिण : प्लॉट 60 फीट का शेष भाग, पूर्व : 20 फीट चौड़ी गली 15 फीट, पश्चिम : अन्य मकान 15 फीट।	28-01-2026 रु. 8,27,080/-	03/01/2026
4.	जसविन्दर सिंह पुत्र राम चंद (कर्जदार), कुलवंत कौर पत्नी जसविन्दर सिंह (सह-कर्जदार), मकान नं. 112/13, सेक्टर-13, जंडवाला मोहल्ला सिरसा, हरियाणा-125056 मोबाइल नं. 9354958406 LHSIR00001324030.	कुलवंत कौर के पक्ष में दस्तावेज नम्बर 6933 दिनांक 24.01.2017 के अनुरूप खन्ना कॉलोनी सिरसा गांव खारपुर तहसील व जिला सिरसा में स्थित भूमि 200 वर्गगज का 1/2 हिस्सा जो सम्पत्ति/प्लॉट नं. 431 माप 100 वर्गगज (उत्तर) है, के सभी भाग व हिस्से। सीमाएं :- उत्तर : प्लॉट नं. 432, 60 फीट, दक्षिण : प्लॉट 60 फीट का शेष भाग, पूर्व : 20 फीट चौड़ी गली 15 फीट, पश्चिम : अन्य मकान 15 फीट।	28-01-2026 रु. 3,62,008/-	03/01/2026
5.	शैलेन्द्र सिंह मोर पुत्र होशियार सिंह मोर (कर्जदार), सुमिता मोर पत्नी शैलेन्द्र सिंह मोर (सह-कर्जदार), बी-1/51, एफएफ डीएलएफ वैली, पंचकूला 134109, हरियाणा NHKTL00001253685.	शैलेन्द्र सिंह के पक्ष में दस्तावेज नं. 638 दिनांक 25.04.2008 के अनुरूप ऋषि नगर-कैथल में स्थित मुरब्बा नं. 158//6/2 का भाग, सम्पत्ति माप 135.47 वर्ग गज के सभी भाग व हिस्से, सीमाएं :- उत्तर : दिगर सम्पत्ति, दक्षिण : गली, पूर्व : दीवार- शैलेन्द्र, पश्चिम : मलखान की सम्पत्ति।	28-01-2026 रु. 4,27,510/-	03/01/2026
6.	शैलेन्द्र सिंह मोर पुत्र होशियार सिंह मोर (कर्जदार), सुमिता मोर पत्नी शैलेन्द्र सिंह मोर (सह-कर्जदार), बी-1/51, एफएफ डीएलएफ वैली, पंचकूला 134109, हरियाणा NHKTL00001253740.	शैलेन्द्र सिंह के पक्ष में दस्तावेज नं. 638 दिनांक 25.04.2008 के अनुरूप ऋषि नगर-कैथल में स्थित मुरब्बा नं. 158//6/2 का भाग, सम्पत्ति माप 135.47 वर्ग गज के सभी भाग व हिस्से, सीमाएं :- उत्तर : दिगर सम्पत्ति, दक्षिण : गली, पूर्व : दीवार- शैलेन्द्र, पश्चिम : मलखान की सम्पत्ति।	28-01-2026 रु. 8,18,624/-	03/01/2026
7.	शैलेन्द्र सिंह मोर पुत्र होशियार सिंह मोर (कर्जदार), सुमिता मोर पत्नी शैलेन्द्र सिंह मोर (सह-कर्जदार), बी-1/51, एफएफ डीएलएफ वैली, पंचकूला 134109, हरियाणा NHKTL00001253741.	शैलेन्द्र सिंह के पक्ष में दस्तावेज नं. 638 दिनांक 25.04.2008 के अनुरूप ऋषि नगर-कैथल में स्थित मुरब्बा नं. 158//6/2 का भाग, सम्पत्ति माप 135.47 वर्ग गज के सभी भाग व हिस्से, सीमाएं :- उत्तर : दिगर सम्पत्ति, दक्षिण : गली, पूर्व : दीवार- शैलेन्द्र, पश्चिम : मलखान की सम्पत्ति।	28-01-2026 रु. 3,61,002/-	03/01/2026

नोटिस की स्थानापन्न सेवा हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/गें और/अथवा उनके गारंटरों (लागू अनुसार) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के अंदर बकाया राशि के भुगतान करने का परामर्श दिया जाता है अन्यथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रत्याभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के अनुरूप आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : 02 फरवरी 2026 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : गोहाना, सोनीपत, सिरसा, कैथल — आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

शब्द पहेली - 6126

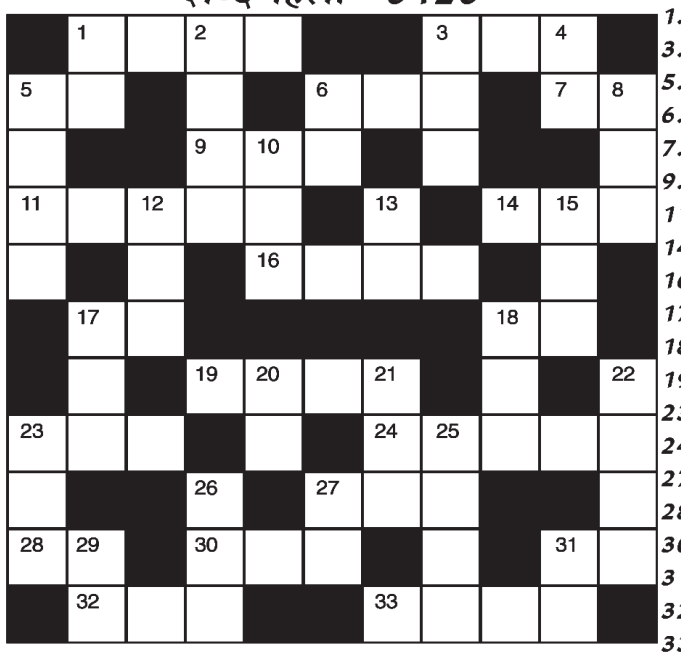

बाएँ से दाए

1. मूर्ख, बुद्धिहीन-4
3. रुई की फसल-3
5. वंश, खानदान-2
6. आह, पीड़ा भरी ध्वनि-3
7. जी, इच्छा, चित्त-2
9. पहनना-3
11. दास, नौकर, सेवक-5
14. अग्नि, आग-3
16. चयनित, स्वीकृत-4
17. जाति, संप्रदाय-2
18. उस समय-2
19. आदत, व्यवहार-4
23. माला का मोती-3
24. लालन-पालन-5
27. पूर्णिमा-3
28. वश, अधीन-2
30. खबर देने वाला-3
31. खदान, माइन-2
32. आश्रय, पनाह-3
33. संपत्ति-4

ऊपर से नीचे

1. घोड़े के पांव में लगने वाला लोहे का टुकड़ा-2
2. धारा के बीच में, अधर में-2,2
3. आफत, आपदा-3
4. एक समान-2
5. गृहपति, चांसलर-4
6. दाना-2
8. प्रतिकृति, प्रतिरूप-3
10. रोकर धनराशि-3
12. प्रेम, आसक्ति-3
13. नीर, जल-2
15. भाग्य, तकदीर-3
17. जंबुल, जांब-3
18. टेंशन, परेशानी-3
20. काया, बदन-2
21. उष्णता-3
22. नाश होने योग्य-4
23. साम्राज्ञी, रानी-3
25. रमण करने योग्य-4
26. अदा, चोंचला-3
27. पूड़ी, गोलगप्पा-2
29. पिता की बहन-2
31. उर्वरक, गाय के गोबर से बना पदार्थ जो खेत में डाला जाता है-2

शब्द पहेली- 6125 का हल

	श	म	शा	न		म	ति	मं	द	
क			य		बी		रं			शे
र		प	र	व	र	दि	गा	र		ता
ता	ड़	ना			वा			ज	वा	न
र		ह		प	र	दा		त	री	
	नी		गै	र		म	जा		स	
	र	वि		म	न	न		स		आ
ग	ज	रा			फा			ह	की	म
र		म	ह	सू	स	क	र	ना		द
म			रा		त		खै			नी
	सो	म	ना	थ		य	ल	गा	र	

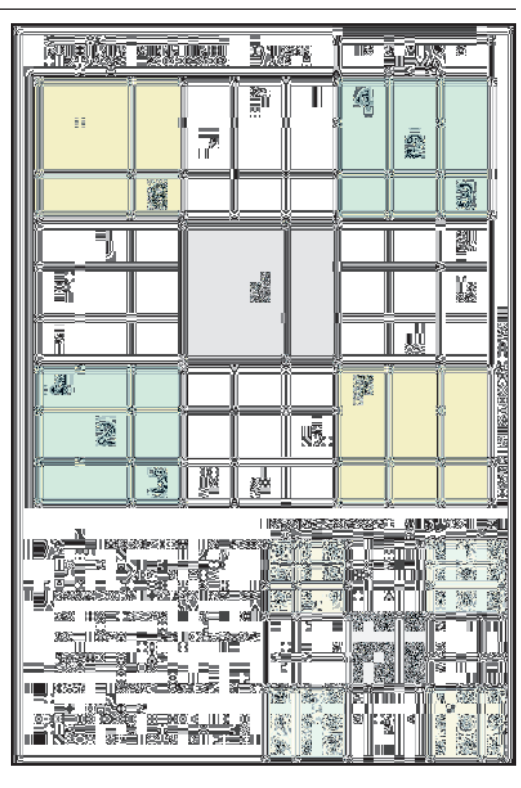

सिरसा में विधायक सेतिया ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की

सीवरेज में पैमाइश करने उतरे मजदूर की मौत, बचाने गया साथी भी बेसुध

■ विभाग ने कहा-बिना किसी को बताए गए थे मजदूर, विधायक ने आर्थिक मदद करने की मांग की

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सिरसा

सिरसा। रस्सी की मदद से मजदूर को सीवर से बाहर निकालते लोग व कर्मचारी।

सिरसा में सीवरेज लाइन में दो मजदूर गिर गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गैस चढ़ने से बेहोश हो गया। उसे बेहोशी की हालत में जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गोलू को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया भी पहुंचे और परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की।

गोलू पुत्र ज्ञान चंद व राजाराम रविवार बाद दोपहर केलनियां रोड पर सीवरेज लाइन की पैमाइश करने गए थे। गोलू सीवरेज लाइन के मेनहॉल में उतर गया और लापता हो गया। उसे बाहर निकालने के लिए राजाराम भी सीवरेज लाइन में उतरा और वह गैस चढ़ने से बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उसे रस्सी की सहायता से बाहर निकाला गया। इसके बाद गोलू की तलाश की गई। करीब डेढ़ घंटे के बाद गोलू का शव मिला। परिवार का आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण गोलू की जान चली गई। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीवरेज लाइन की पैमाइश हो चुकी थी और ठेकेदार के कर्मचारियों को कुछ उलझन थी और वे बिना अधिकारियों व ठेकेदार को बताए सीवरेज लाइन में पैमाइश के लिए गए थे।

विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा जाएगा और हमारी तरफ से भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एसवाईएल पुल पर पेंट करते हुए डूबे दो पेंटर, दूसरे दिन भी की तलाश

अंबाला। कुरुक्षेत्र जिले में बटेडा हेड पर सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर बने लोहे के पुल को पेंट करने के दौरान अंबाला के गांव भून्नी के दो युवक नहर में गिर गए। तेज बहाव की वजह से दोनों पानी में लापता हो गए। अभी तक दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है। गोताखोगर प्रगट सिंह और उनकी टीम उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के मुताबिक, डूबने वाले दोनों युवक गुरविंद्र सिंह (22) और सागर (20) हैं। वे अपने साथी सोहेल और अन्य के साथ बटेडा हेड पर लोहे के पुल को पेंट करने के लिए आए थे। दोनों पूल पर शटरिंग लगाकर अपना काम कर रहे थे। अचानक शटरिंग का पाइप खुल जाने से सागर पांव फिसलने से सीधे नहर में गिर गया। सागर को डूबता देखकर गुरविंद्र उसे बचाने के लिए नहर में उसके पीछे कूद गया। गुरविंद्र को तैरना आता था। उसने सागर को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन डर के कारण सागर ने उसे कसकर पकड़ लिया। इससे दोनों नहर में डूबने लगे। दोनों को डूबता देख साथियों ने शोर मचा दिया। सोहेल ने रस्सी फेंककर कोशिश की, लेकिन वे नहर में पानी के साथ आगे बहने लगे। फिर सोहेल भी उनको बचाने के लिए नहर में उतर गया, मगर तब तक दोनों बह चुके थे।

इंस्टाग्राम पर लड़की बन ठगने वाले काबू

जींद। इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने के दो आरोपितों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 23500 रुपये बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ इससे पहले भी नारनौल व कैथल में मामले दर्ज हैं। जींद पुलिस दोनों को कैथल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर वापस जेल भेज दिया है। आरोपितों की पहचान फरीदाबाद एनआईटी की पर्वतीय कॉलोनी निवासी विपिन सारस्वत व संजय इन्कलेव एनआईटी फरीदाबाद निवासी कौशल के रूप में हुई है।

साइबर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर 2025 को लक्ष्मी नगर निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत दी थी। अंकित ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर एक लड़की से बातचीत शुरू हुई। लड़की ने अपने आपको मथुरा निवासी बताया और कहा कि उसके पिता सियाचीन में आर्मी अफसर हैं। बातचीत के बाद लड़की ने कभी ट्रिप फीस, बीमारी और एक्सीडेंट का बहाना बना तीन लाख 51 हजार 490 रुपये ठग लिए। दूसरा व्यक्ति लड़की का पिता बनकर अंकित को जल्द ही पैसे लौटाने की बात कह देता।

बैंक में रखा सोना भी सुरक्षित नहीं

सीए का डेढ़ करोड़ का सोना चांदी बैंक लॉकर से गायब

■ बैंक ने सरेंडर होने का दावा किया, सीए ने कहा-लॉकर की चाबी हमारे पास तो सरेंडर कैसे

हरिभूमि न्यूज ▶▶| फरीदाबाद

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेक्टर 15 शाखा से सोने-चांदी के आभूषणों से भरा एक पूरा लॉकर ही गायब हो गया। सीए व उनके परिवार का दावा है कि उनके लॉकर में करीब एक किलो सोने और करीब तीन किलो चांदी के गहने बैंक ने गायब कर दिए। जब उनकी पत्नी इसे चेक करने गई तो बैंक कर्मचारी ने कहा कि उनका लॉकर तो पहले ही बंद हो चुका है। जब उसकी चाबी हमारे पास थी। हमने लॉकर कभी बंद नहीं करवाया। इसमें बैंक की मिलीभगत है। जेवर की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है।

सीए डीसी गर्ग ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है, जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। पुलिस चौकी सेक्टर 15 इंचार्ज ओमप्रकाश ने बताया कि सीए डीसी गर्ग की ओर से दी गई शिकायत पर बैंक अफसरों से संपर्क किया गया। बैंक अफसरों की ओर से उन्हें बताया गया है कि डीसी गर्ग द्वारा लॉकर को सरेंडर कर दिया गया था। पुलिस ने बैंक को नोटिस जारी कर सरेंडर पेपर मांगे हैं।

एक किलो सोना व तीन किलो चांदी थी

सेक्टर-15ए निवासी सीए डीसी गर्ग ने बताया कि उनका एसबीआई सेक्टर-15 ब्रांच में वर्ष 2014 से अकाउंट है। नियमित रूप से उनका लॉकर शुल्क 2300 रुपये सालाना कटता है। लॉकर की मूल चाबी भी हमारे पास है। लॉकर में लगभग एक किलो सोने और करीब तीन किलो चांदी के गहने रखे थे। डीसी गर्ग ने बताया कि करीब आठ महीने पहले उन्होंने आखिरी बार लॉकर का इस्तेमाल किया था। अब उन्हें कहा जा रहा है कि उनका बैंक लॉकर तो बंद हो चुका है। उन्होंने लॉकर बंद करवाने से इंकार किया और बैंक से बंद करने की प्रक्रिया से संबंधित कागजात मांगे। संतुष्टि न होने पर उन्होंने इसकी शिकायत सेक्टर 15 पुलिस चौकी को दी।

शीत लहर का प्रकोप

कलायत के सिंणद में 50 मवेशी की मौत से हड़कंप, पहुंचे डॉक्टर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| कलायत

कलायत के गांव सिंणद में पिछले करीब दो सप्ताह से फैली एक अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। रहस्यमयी बीमारी के चलते अब तक करीब 50 भैंसों और कटड़ों की मौत हो चुकी है। जिससे ग्रामीणों में भारी डर और दहशत का माहौल है। पशुपालक शमशेर, सतपाल, सूरजभान, राजेश, पाल, बलराज व अन्य ने बताया कि उनके पशु इस बीमारी की भेंट चढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में पहले पशु को तेज बुखार आता है व फिर वह चारा छोड़ देता है। इसके बाद सांस लेने की गति तेज हो जाती है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लक्षण दिखने के मात्र 10 से 12 घंटे के भीतर पशु दम तोड़ देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया है। पशु चिकित्सक डॉ. हरीश रोहिल्ला ने बताया कि शुरुआती जांच में यह समस्या शीत लहर के कारण फेफड़ों में हुए गंभीर संक्रमण की लग रही है। विभाग द्वारा सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने और पीड़ितों किसानों को मुआवजे की मांग की है।

3 दिन दवा का कोर्स करें

डॉ. हरीश रोहिल्ला ने सलाह दी कि पशुओं के बाड़े में नीचे सूखा रखें, उन्हें कपड़े या पल्ली से ढककर ठंड से बचाएं और फर्श पर चूने का छिड़काव करें। जिन पशुओं का उपचार चल रहा है उन्हें कम से कम 3 दिन तक दवाइयों का पूरा कोर्स दिया जाए। प्रशासन ने संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस ने मेडिकल नशे की चेन तोड़ी, 2 काबू

कैथल। 2500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले की जांच सीआईए-1 प्रभारी एसआई जसवंत सिंह की अगुवाई में एएसआई गुरदान सिंह की टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम ने आरोपी गांव बेलड़ा यूपी निवासी राहुल व हिमांशु को काबू कर रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 28 नवंबर को सीआईए-1 पुलिस के एएसआई प्रवीन कुमार की टीम द्वारा गांव पहाड़पुर से गांव चक्कू लदाना जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी करके पैदल आए आरोपी चक्कू लदाना निवासी रवि को काबू किया गया था, जिसके कब्जे में पॉलीथिन में 5 डिब्बों से ट्रामाडोल नामक 2500 गोलियां बरामद हुई थी। थाना सीवन में दर्ज मामले की आगामी जांच एएसआई गुरदान सिंह द्वारा अमल में लाई गई। आरोपी रवि से पूछताछ दौरान खुलासा हुआ था कि उसको यह गोलियां दिवांशु उर्फ विशु द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। आरोपी दिवांशु उर्फ विशु से व्यापक पूछताछ के दौरान सामने आया कि उसको यह गोलियां माता गेट कैथल निवासी प्रवीन कुमार द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी तथा प्रवीन को यह गोलियां विभांशु उर्फ छोटू द्वारा सप्लाई की गई थी। आरोपी विभांशु उर्फ छोटू को पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आगामी जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी हिमांशु यूपी में केमिस्ट की दुकान करता है तथा राहुल उसका भाई है। राहुल द्वारा विभांशु उर्फ छोटू को यह गोलियां सप्लाई की गई थी।

रवि को पकड़ा तो आया दिवांशु, प्रवीण, विभांशु, हिमांशु व राहुल का नाम

पं. जसराज जयंती पर फतेहाबाद में आज समारोह

सोनू निगम और अनूप जलोटा समेत नामी कलाकार देंगे सुरों से श्रद्धांजलि

हरिभूमि न्यूज ▶▶| फतेहाबाद

■ पीलीमंदोरी में हुआ था पंडित जसराज का जन्म, पद्मश्री और विभूषण से हो चुके हैं सम्मानित

भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमूल्य धरोहर, मेवाती घराने के महान साधक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज की जयंती के अवसर पर 2 फरवरी को फतेहाबाद जिला के ऐतिहासिक गांव पीलीमंदोरी में सुबह 11 बजे एक भव्य राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले पंडित जसराज का जन्म इसी गांव पीलीमंदोरी में हुआ।

समारोह में देश एवं प्रदेश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, भजन गायक एवं लोक कलाकार अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से पंडित जसराज को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में मुंबई से पंडित जसराज के परिजन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम, भजन गायक अनूप जलोटा सहित अनेक नामचीन कलाकार भाग लेंगे।

मेवाती घराने से थे

पिता पंडित जसराज के पिता मोतीराम मेवाती घराने से जुड़े हुए थे। वह हैदराबाद के निजाम के गवैये थे। इसके चलते उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया। उस समय पंडित जसराज की उम्र मात्र 7 साल की ही थी। पंडित जसराज ने भी मेवात घराने को आगे बढ़ाया और खूब नाम कमाया।

चिंतन

आम बजट में भविष्य की तस्वीर दिखाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026 एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज़ है, जो भारत को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। यह बजट विकासोन्मुखी,दीर्घकालिक सोच, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह आम आदमी की तात्कालिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कमजोर भी नजर आता है। कहा जा सकता है कि यह बजट "कल" की तैयारी करता है, पर "आज" की परेशानियों को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। वित्त मंत्री ने 85 मिनट के लंबे भाषण में अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विस्तार से बात की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में आम करदाता को इससे सीमित ही राहत मिलेगी। बजट का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा क्षेत्र है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये करना और आधुनिकीकरण व हथियार खरीद पर पूंजीगत खर्च में करीब 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार सेना को तकनीकी और रणनीतिक रूप से और सक्षम बनाना चाहती है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, हालांकि सामाजिक क्षेत्रों में इसी अनुपात में खर्च न बढ़ना सवाल भी खड़े करता है। अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के प्रयास बजट में साफ झलकते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ट्रंप-युग की टैरिफ मानसिकता और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में तनाव के बीच निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, फिशरीज और दालों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पतालों की घोषणा, दवाओं को सस्ता करने की पहल और 17 कैंसर मेडिसिन को ड्यूटी फ्री करना आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। आयुर्वेदिक एम्स जैसी घोषणाएं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती हैं। शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित योजनाएं बजट का एक और उल्लेखनीय पहलू हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा सामाजिक समावेशन और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बजट चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं से दूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद किसी सीधे चुनावी लाभ वाली घोषणा का अभाव बताता है कि सरकार फिलहाल दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है। यह बजट लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो मजबूत रक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

विश्लेषण

डॉ.जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के समक्ष बजट तैयार करते समय चुनौतियां भी रही हैं। इन चुनौतियों में रुपये में लगातार गिरावट, अमेरिका का ऊंचा टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग व कृषि की धीमी रफ्तार शामिल हैं। निसंदेह वित्त मंत्री बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को बढ़ाते हुए दिखाई दी हैं। बजट में रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बजट में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और

क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के सुधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी रणनीतियां भी दिखाई दी हैं। युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। सीतारमण बजट में खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए भी आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ी हैं। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति भी अपनाई है। विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहे हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार में और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है।

भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। यह बजट इसलिए भी खास रहा है, क्योंकि यह बजट पुराने टैक्स युग से नए टैक्स युग की दहलीज पर खड़ा बजट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स कानून लागू किया है। इससे देश के करोड़ों आयकरदाता लाभांवित होंगे। साथ ही नई श्रम संहिताएं भी आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होने से श्रम उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास का नया अध्याय दिखाई देगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। इस बजट से जहां देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू हो सकेगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा।

उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

आम बजट

प्रमोद भार्गव

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। इसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग,प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री,जैविक दवाओं,कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है।

इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ जीवन की आधारशिला

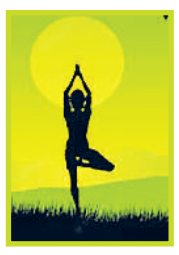

संकलित

दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

मन का भोजन हमारे विचार

संकलित

प्रेरणा

एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच-विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न तीन बार पूछा था और बुद्ध ने भी तीन बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने तीन बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी तीन बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से तीन बार प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी तीन बार दिया, ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए।

अंतर्मन

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते कई बार हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिडकी जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। - *संजय शर्मा, दुर्ग*

ट्रेंड

बालिका छात्रावास बड़ा निर्णय

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा ! केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण का बड़ा निर्णय लिया है। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला एक मील का पत्थर है।

-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

अमल भी जरूरी

बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के सम्बन्ध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े-बड़े हैं, किन्तु जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे ना हो तो बेहतर होगा। केवल बाते न हों, इन पर सही नीयत से अमल भी जरूरी है।

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

निराशाजनक रहा बजट

बजट संबंधी दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन करना अभी बाकी है, फिर भी बजट को लेकर जो उम्मीदें की गई थीं, उन पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। यह पूरी तरह फीका और निराशाजनक रहा।

- जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

विकासोन्मुखी बजट

विकासोन्मुखी बजट, जिसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट युवाओं को आजीविका सुधारने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा।

- अनिल अग्रवाल, उद्यमी

करंट अफेयर

इजराइल की रफाह सीमा क्रॉसिंग खोलने की घोषणा

इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गयी। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी यहां से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी मिस्र वाले द्वार से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी द्वार की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एंबुलेंस भी मिस्र वाले द्वार से होकर गुजरीं।

ऑफ बीट

रात में पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं

पसीना आना शरीर की शीतलन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है, जो गर्मी छोड़ने और शरीर के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।

लेकिन नियमित रूप से रात में जागना, अत्यधिक पसीने से भीगना सही नहीं है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, अंत:स्रावी तंत्र का हिस्सा है और शरीर के लिए तापमान नियंत्रण केंद्र है। इसमें तापमान सेंसर होते हैं जो केंद्रीय रूप से (अंगों में) और परिधीय रूप से त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं (थर्मोरिसेप्टर्स) से जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स शरीर के तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, हाइपोथैलेमस को वापस संकेत भेजते हैं। ये संकेत या तो शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को सक्रिय करेंगे या शरीर को गर्म करने के लिए कंपकंपी को सक्रिय करेंगे। उम्र या लिंग कोई भी हो, किसी को भी रात में पसीना आने का अनुभव हो सकता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रात में पसीना अधिक आता है, इसका मुख्य कारण रजोनिवृत्ति और संबंधित बदलते हार्मोन स्तर हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हाइपोथैलेमस में तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं।

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20

ई-मेल : haribhoomi@gmail.com

वेब-साइट : www.haribhoomi.com

बजट: खेल सामग्री क्षेत्र के लिए 500 करोड़, खेलो इंडिया को फिर से सर्वाधिक आवंटन

एजेंसी ▶▶| नयी दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है क्योंकि उसको पहली बार 500 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपये है जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपये से 1133.34 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटित राशि को 880 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशभर के स्टेडियमों के रखरखाव और उनके उपयोग की जिम्मेदारी भी साइ की होती है। हालांकि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी का बजट क्रमशः 28.55 करोड़ रुपये से घटाकर 23 करोड़ रुपये और 24.30 करोड़ रुपये से घटाकर 20.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर जोर दिया और इस तरह से खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ''मैं खेल सामग्री के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं जिससे उपकरण डिजाइन के साथ-साथ खेल सामग्री के क्षेत्र में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।''

खेल इकाइयों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि की सूची

▶▶| खेलो इंडिया मिशन	924.35 करोड़
▶▶| भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)	917.38 करोड़
▶▶| खेल सामग्री निर्माण	500.00 करोड़
▶▶| राष्ट्रीय खेल संघ	425.00 करोड़
▶▶| मेरा युवा भारत	655.22 करोड़
▶▶| कॉमनवेल्थ गेम्स 2026	50.00 करोड़
▶▶| खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	40.00 करोड़

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि 50 करोड़ हुई

अभी तक के बजट में खेल सामग्री क्षेत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया और कहा कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस पहल से 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत देश में खेल सामग्री निर्माण करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार के 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के लिए 924.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके लिए पिछले वर्ष आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपये थी, लेकिन अंतिम व्यय 700 करोड़ रुपये रहा। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28.05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होंगे।

खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 40 करोड़ की

राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान राशि को तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता राशि में भी मामूली वृद्धि की गई है, जो 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा, ''यह मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल संरचना के विकास को सुगम बनाएगा।''

'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव

सीतारमण ने अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, ''खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।''

कुश्ती कोच की नजर में बजट

कुश्ती कोच मनदीप ने बताया कि खेलो इंडिया को मिशन मोड में लाना यह दर्शाता है कि सरकार केवल प्रतिभा खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 10 वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे, खेल विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण को एकीकृत कर रही है। यह जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को 28 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता राशि में वृद्धि करना यह सुनिश्चित करेगा कि एथलीटों को उनकी मेहनत का उचित सम्मान और ट्रेनिंग के लिए जरूरी संसाधन मिलते रहें। युवा हॉस्टलों के बजट में 1.10 करोड़ से सीधे 19.20 करोड़ की बढ़ोतरी और एनएसएस के बजट में वृद्धि दर्शाती है कि सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेल अनुशासन को लेकर गंभीर है।

खबर संक्षेप

महिला अंडर-17 टीम के सामने बांग्लादेश की चुनौती

पोखरा। भारतीय टीम सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अपने दूसरे मुकाबले में सोमवार को जब पोखरा रंगशाला स्टेडियम में मजबूत बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश एक मैच शेष रहते फाइनल में जगह पक्की करने की होगी। इस साल के आखिर में चीन में होने वाले एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारियों में लगी पामेला कॉन्टी की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान नेपाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 की जीत के साथ की थी। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतने में सफल रही तो फाइनल के लिए उसका दावा लगभग पक्का हो जाएगा। भारत को इससे पहले मेजबान नेपाल से कड़ी चुनौती मिली लेकिन पर्ल फर्नांडिस ने 49वें मिनट में गोल कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया।

जूनियर पुरुष स्कीट टी2 ट्रायल में पंजाब के निशानेबाज शीर्ष पर

नई दिल्ली। पंजाब के हरवीराज सिंह, हरजीज सिंह अटवाल और गुरफतेह सिंह संधू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर शॉटगन राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स एक और दो में जूनियर पुरुष स्कीट टी2 के फाइनल में क्लीन स्वीप किया। अनंतजीत सिंह

नरूका ने पुरुष वर्ग के ट्रायल दो फाइनल में 36 में से 36 का परफेक्ट स्कोर कर ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को एक अंक से पछाड़ते हुए खिताब जीता। यशस्वी राठौड़ ने महिला ट्रायल्स दो में सिर्फ एक निशाना चूकते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वालीफिकेशन में 120 अंक के साथ शीर्ष पर रहने वाले अनंतजीत ने फाइनल में सटीक प्रदर्शन किया। ज्योतिरादित्य ने भी 34वें टारगेट तक परफेक्ट स्कोर बनाए रखा, लेकिन 35वें निशाने में चूकने के कारण 36 में से 35 अंक ही हासिल कर सके। अभय सिंह सेखों ने 30 निशाने के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों को करना होगा दिनचर्या में बदलाव : सैंटनर

तिरुवनंतपुरम। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उपमहाद्वीप में अपने पिछले अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की अपनी

क्षमता पर भरोसा करेगी। न्यूजीलैंड ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। सैंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने हाल आईपीएल में या अपने करियर के दौरान चेन्नई में मैच खेले हैं। उन्होंने कहा, 'दिन का खेल थोड़ा अलग होने वाला है। खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। उन्हें थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक नई चुनौती है।

22 साल के अल्कारेज ने एक सेट गंवाने के बाद की वापसी, जोकोविच को दी शिकस्त

अल्कारेज ने कम्पलीट किया कॅरियर स्लैम, तोड़ा जोकोविच का सपना, जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

कार्लोस अल्कारेज रविवार को फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे कॅरियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। 22 साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा।

कोच को गले लगाने दौड़े कार्लोस

जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा।

■ कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस

अल्कारेज ने तोड़ा डॉन बज का रिकॉर्ड

अल्कारेज 22 साल और 272 दिन की उम्र में चारों ग्रैंडस्लैम का एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 1938 की फ्रेंच चैंपियनशिप में डॉन बज का बनाया रिकॉर्ड तोड़ा जब वह 22 साल और 363 दिन के थे। स्पेन के अल्कारेज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अलावा दो-दो विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम पर अल्कारेज ने लगाई रोक

दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा पाक

पाकिस्तान सरकार का ऐलान, टूर्नामेंट में भाग लेगा

एजेंसी ▶▶| कराची

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ''मैदान पर नहीं उतरेगी''।

पाक के बहिष्कार के नतीजेः प्रतिबंध, नुकसान की भरपाई, पीएसएल पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक नहीं

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम उठा सकता है। यह कार्रवाई पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बाद की जा सकती है और इसमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आगामी सत्र से टीम पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। अन्य सजा में शीर्ष सदस्य देशों का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने से इनकार करना, भारी वित्तीय जुर्माना और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के फैसले का साथ देते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप लीग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है जबकि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उसका तटस्थ स्थल पर मैच खेलने का अनुबंध है जो बाध्यकारी है। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है लेकिन चूंकि आधिकारिक घोषणा हो चुकी है इसलिए आईसीसी के कुछ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है।

स्क्वैश ऑन फायर

सबरीना को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं अनाहत

एजेंसी ▶▶| वाशिंगटन

अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोभी को 3-1 से मात दी। इसी के साथ अनाहत ने पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 23 सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबले में 17 वर्षीय अनाहत का सामना टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जीना कैनेडी से होगा। इससे पहले, शनिवार को अनाहत ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए नंबर 2 सीड सना इब्राहिम को शिकस्त देकर स्क्वैश ऑन फायर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय वर्ल्ड नंबर 31 और सातवीं सीड खिलाड़ी ने मैच में वापसी करते हुए, तीसरे और चौथे गेम दोनों में 6-5 के घाटे को पलट दिया, और पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट में मिस्र की वर्ल्ड नंबर 17 सना इब्राहिम को 8-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-7 से मात दी थी।

बल्लेबाजी में बदलाव से मिली फॉर्म में वापसी में मददः सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली। सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया।'

अंडर-19 विश्व कपः कनिष्क के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

भाषा ▶▶| बुलावायो

युवा कनिष्क चौहान के हरफनमौला खेल के दम पर भारत ने अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में रविवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत के सामने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती होगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगे। कनिष्क ने बल्ले से 29 गेंद में 35 रन की पारी खेलने के अलावा आठवें विकेट लिए खिलान पटेल (15 गेंद में 21 रन) के साथ 50 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की जिससे टीम ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाये। पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था लेकिन टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने 33.3 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बनाये थे और फिर पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर आउट हो गयी। गेंदबाजी विभाग में कनिष्क ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर एक विकेट चटकाते हुए पाकिस्तान टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने इस दौरान 40 डॉट गेंदें डाली। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के बीच बाएं हाथ के स्पिनर खिलान पटेल (9.2 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान आयुष म्हात्रे (8 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी बीच ओवरों में रन गति को पूरी तरह बांधे रखा।

■ पाकिस्तान को 58 रन से हराया
■ वेदांत की फिफ्टी, आयुष म्हात्रे और खिलन पटेल को 3-3 विकेट

गेंदबाजों और वोल्टवार्ट ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत और एलिमिनेटर में जगह दिलाई

वडोदरा। मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन के बाद लॉरा वोल्वार्ट की उम्दा पारी से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में रविवार को यहां यूपी वारियर्स को पांच विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बनाई। दिल्ली की टीम अब एलिमिनेटर में मंगलवार को गुजरात जाइंट्स से भिड़ेगी। वारियर्स के 123 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने दो जीवनदान का फायदा उठाने वाली वोल्वार्ट की 36 गेंद में सात चौकों से 47 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (29 रन, 33 गेंद, दो चौके) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से 18.4 ओवर में पांच विकेट पर 126 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 18 गेंद में पांच चौकों से नाबाद 34 रन की पारी खेलकर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत से आठ अंक के साथ मुंबई इंडियन्स (छह अंक) को पछाड़कर तीसरे स्थान पर रहते हुए एलिमिनेटर में जगह बनाई। रॉयल

चैलेंजर्स बेंगलुरु (12) और गुजरात जाइंट्स (10) शुरुआती दो स्थान पर रहे। कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और चिनेल हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वारियर्स की टीम आठ विकेट पर 122 रन ही बना सकी।

थाईलैंड मास्टर्स में हटी दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह

देविका ने जीता अपना पहला सुपर 300 खिताब

एजेंसी ▶▶| बैंकॉक

युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही।

देविका के लिए फाइनल रहा शानदार

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह लगातार परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया।

मलेशियाई खिलाड़ी लग रही थीं थकी हुई

मलेशियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के खेल को समझ ही नहीं पा रही थी। मलेशियाई खिलाड़ी थकी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें ऊर्जा नहीं बची है। देविका ने शानदार क्रॉस के दम पर 13 गेम प्वाइंट हासिल किए और बैकहैंड क्रॉस से पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में देविका ने जल्द ही 6-3 की बढ़त बना ली। मलेशिया की खिलाड़ी असहज दिख रही थी और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला कर दिया। देविका ने पिछले कुछ समय से शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अगस्त 2025 में मलेशिया इंटरनेशनल में अपना पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने 2025 में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत की मिश्रित टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम योगदान दिया। वह पिछले सत्र में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रही थी जबकि 2024 में चार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इनमें स्वीडिश ओपन और पुर्तगाल इंटरनेशनल भी शामिल हैं, जहां वह विजेता रही थी।

खबर संक्षेप

मणिपुर के 20 विधायकों की दिल्ली में मीटिंग

नई दिल्ली। मणिपुर के 20 से अधिक भाजपा विधायकों ने रविवार को राज्य इकाई के अध्यक्ष के साथ

इंफाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक में शामिल होंगे। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिराजमायुम शारदा देवी ने कहा कि सभी एनडीए विधायकों को बुलाया गया है। प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग, गिरफ्तार

मुंबई। यहां के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने

आई है। जिस समय यह फायरिंग हुई, उस वक्त शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था।

ट्रंप की पत्नी मेलानिया की फिल्म रही फ्लाप

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री 'मेलानियाः 20 डेज

टू हिस्ट्री' शुक्रवार को रिलीज हुई। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुई। मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री में जनवरी 2025 में डोनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से ठीक 20 दिन पहले की कहानी दिखाई गई है।

रांची के मां-बेटे की पुरी समुद्र में दर्दनाक मौत

रांची। ओडिशा के पुरी में छुट्टियां मनाने आए रांची के एक प्रतिष्ठित परिवार के लिए शनिवार काल

बनकर आया।चक्रतीर्थ रोड स्थित पिंक हाउस क्षेत्र में समुद्र स्नान के दौरान मां को डूबता देख उसे बचाने कूदा इकलौता बेटा भी लहरों की भेंट चढ़ गया। इस हृदयविदारक घटना ने जहां रांची के आरएसएस परिवार में शोक की लहर दौड़ा दी है।

विजया 2 मासूम बच्चों संग ट्रेन के आगे कूदी

हैदराबाद। यहां रविवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास

38 साल की पी. विजया ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार रात करीब 12:40 बजे की है, जब सनतनगर जा रही मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। मामले की जांच की जा रही है।

पत्रकारों से बातचीत में कहा-हमने पहले ही डील तय कर ली

भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल, डील हो गई पक्की

अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन/ नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तेल खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस बारे में डील की गई है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही वह डील कर ली है। डील का कॉन्सेप्ट तय हो गया है। ट्रंप का बयान अमेरिका के नई दिल्ली को यह संकेत देने के एक दिन बाद आया है कि वह रूसी कच्चे तेल के कम आयात की भरपाई के लिए जल्द ही वेनेजुएला से तेल खरीदना फिर से शुरू कर सकता है।

खामेनेई की सबसे खतरनाक धमकी

हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में होगी क्रांति

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है।

अमेरिका जान ले यह क्षेत्रीय युद्ध होगा

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसाने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या उसे परेशान करेगा।

एनसीबी के विलय पर असमंजस की स्थिति बरकरार

शपथ ग्रहण पर राकांपा प्रमुख ने दिया स्पष्टीकरण

शरद पवार मुंबई पहुंचे तो बारामती लौट गईं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार

एजेंसी ▶▶ मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच, एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार रविवार सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देर रात बारामती लौट आईं। शरद पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चार दिन बाद मुंबई के लिए रवाना हुए। सुनेत्रा ने शनिवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास लौट आईं।

शपथ ग्रहण पर मुझसे बात नहीं हुईः शरद

सुनेत्रा के शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई। यह फैसला पार्टी ने स्वयं लिया होगा। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पहल की होगी और संभव है कि पार्टी के भीतर ही यह निर्णय लिया गया हो।

12 फरवरी को होने वाला था विलय

शरद ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अजित पवार ने 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की घोषणा करने की तारीख तय की थी।

बजट में भूटान, श्रीलंका व अफ्रीकी देशों को मदद के लिए राशि का ऐलान

बांग्लादेश के लिए सहायता में की कटौती, साथ ही चाबहार बंदरगाह पर आवंटन का कॉलम 'गायब'

पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है। भूटान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर अफ्रीकी देशों तक की मदद के लिए राशि का ऐलान किया गया है। हालांकि, बांग्लादेश के लिए सहायता राशि में कटौती की चर्चा है। पिछले कुछ समय से भारत के बांग्लादेश के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। इस बजट में एक चौंकाने वाली बात यह रही कि चाबहार बंदरगाह के लिए सहयोग राशि वाली पंक्ति को 2026-27 के लिए खाली छोड़ा दिया गया।

पड़ोसी देशों के रिश्तों को परखा

चाबहार बंदरगाह परियोजना

विदेश की बाकी योजनाओं पर ऐसा रहा बजट

- केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय से जुड़े सचिवालयों के लिए 761.21 करोड़ का बजट तय किया।
- दूतावासों-मिशन्स के लिए 5059.30 करोड़ तय किए गए।
- पासपोर्ट और आव्रजन व्यवस्था के लिए 2435.13 करोड़ आवंटित किए गए।
- विदेश में रह रही भारतीय महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लिए पांच करोड़ दिए गए।
- मंत्रालय के अन्य खर्चों के लिए 1265 करोड़ बजट में रखे गए हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों/ट्रेनिंग के लिए 1292 करोड़ तय किए गए हैं।

इन देशों की मदद पिछले साल के मुकाबले परिवर्तित की

लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को दो गुना किया

मंगोलिया के बजट में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को सीधे दोगुना कर दिया गया है। सरकार दक्षिण अमेरिका में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर दे रही है।

आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने इस बार राशि में किया इजाफा

भारत ने विदेश में आपदा प्रबंधन के लिए सहायता के तौर पर 2025-26 के 64 करोड़ के मुकाबले 2026-27 में 80 करोड़ की राशि आवंटित की है। भारत ने बीते साल इस राशि के जरिए श्रीलंका की दित्वाह चक्रवात से निपटने में मदद की। म्यांमार और अफगानिस्तान की भूकंप के बाद हुई तबाही से निपटने में भी मदद की गई। सरकार ने इस राशि के जरिए कुछ देशों को राहत सामग्री भी पहुंचाई है।

पीएम मोदी ने लुधियाना को दी सौगात

हलवारा एयरपोर्ट का लोकार्पण अगले माह से होगा संचालन

एजेंसी ▶▶ लुधियाना

कई वर्षों के इंतजार के बाद लुधियाना के लोगों को नया एयरपोर्ट मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवार को लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर शहर को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अब और आसान हो जाएगी। मार्च से हलवारा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से लुधियाना के बीच सप्ताह में पांच दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स चलाई जाएंगी।

संत निरंजन दास के पैर छुए

प्रधानमंत्रीरविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां संत निरंजन दास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया।

आमजन को झटका, अब 1,740.50 रुपये में मिलेगी गैस

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हो गया 49 रु. का इजाफा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 फरवरी से लागू हो गई है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी

सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब बढ़कर 1,740.50 रुपए हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों के रसोई का बजट बिगड़ सकता है।

प्रवक्ता जायसवाल ने पाकिस्तान की खोली पोल

92 बलूच विद्रोहियों को मारने का किया दावा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पाकिस्तान बोला- 18 सैनिक मारे गए

- घर में आग और भारत पर भड़ास निकाल रहा पाक
- बलूचिस्तान में सैनिकों के ढेर होने पर बोला पाक

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इन हमलों में 80 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने दावा करते हुए कहा है कि उसके 18 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 92 बलूच विद्रोही मारे गए हैं। पाक ने अपने घर में लगी आग के लिए भारत पर भड़ास निकाली है। चीन के हस्तक्षेप, सीपीईसी प्रोजेक्ट और ग्वादर बंदरगाह के लिए बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन निवासियों की जिंदगी बदतर है। इसी के विरोध में बलूच विद्रोही संगठन अकसर पाकिस्तानी सेना, पंजाबी मूल के लोगों और यहां तक की चीनी नागरिकों पर भी निशाना साधते रहते हैं।

इस बार बलूचों ने किया सबसे बड़ा अटैक

कई बार बलूच विद्रोही संगठनों ने खूनी हमले भी किए हैं। इस बार अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक अटैक किया है। पाकिस्तान इन हमलों की वजह तलाशने की बजाय भारत पर ही भड़ास निकाल रहा है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा यूनिट आईएसपीआर ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिश की है। उसने कहा कि ये हमले भारत से मदद पाने वाले फितना-अल-हिंदुस्तान नाम के संगठन ने किए हैं। ये हमले क्वेटा, मस्तंग, नुशकी, दलबंदीन, खारन, पंजगुर, ग्वादर और पसनी में हुए हैं।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक देवेन्द्र सिंह द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड़, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 से प्रकाशित। संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। RNI No. 63924/1996, फोन : 9253681019-20, फैक्स : 274202, e-mail : rohtak@haribhoomi.com, rohtakharibhoomi@gmail.com
Postal Regd. No. P/RTK/389/2026-28